RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹: 30/-

प्रेरणा विचार

मासिक
भाद्रपद-आश्विन, विक्रम संवत् 2082 (सितम्बर -2025)
पृष्ठ-36, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

100 वर्ष की संघ यात्रा

नए क्षितिज

- N.C.C., Scout & Guide
- Shooting Range
- Library
- First Aid & Medical Facilities
- Digital White Board & Smart Board
- Online Learning Platform
- Cultural Activity Hall & Auditorium
- Atal Tinkering Lab. for Robotics & innovation
- Well Equipped Laboratory
- National Rank in Sports Competition

BHAURAV DEVRAS
SARASWATI VIDYA MANDIR

H-107, Sector-12, NOIDA
E-Mail: bdsvidyamandir@gmail.com
Contact No. 0120-423817, 9910665195
Website: www.bdsvidyamandirnoida.com
Facebook: bdsvidyamandirnoida
YouTube: BDSVM

प्रेरणा विचार

वर्ष -3, अंक - 09

RNI No. UPHIN/2023/84344

संरक्षक
अनिल त्यागी

प्रबंध निदेशक
बिजेन्द्र कुमार गुप्ता

सलाहकार मंडल
श्याम किशोर, डॉ. अनिल निगम
अशोक सिन्हा

संपादक
डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक
मोनिका चौहान

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62,
नोएडा - 201309
दूरभाष : 0120 4565851
मोबाइल : 9354133708,9354133754
ईमेल : prernavichar@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा।

संपादक

इस अंक में

100 वर्ष की संघ यात्रा
'नए क्षितिज' - 05

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020
पांच वर्षों की यात्रा और प्रासंगिकता -11

अंत्योदय से भारत निर्माण -18

लव जिहाद
हिन्दू क्यों हार रहा नेरेटिव की लड़ाई- 24

सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया का नाम संघ है -....................................09

अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता..........................14

हिंदी पत्रकारिता के 200 साल..16

क्यों बढ़ रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में आपदायें?...20

सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति : भारत की रैंकिंग में बढ़ोतरी...........................22

विभिन्न समुदायों को उत्सवों के लिए एक साथ लाता सितम्बर............................26

'फास्ट' से पहचानें स्ट्रोक के लक्षण 28

पर्यावरण जागरूकता के लिए समर्पित पीपल मैन...29

मध्यमवर्गीय परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध... 30

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा -100 साल की सेवा यात्रा है संघ की....31

आत्मनिर्भरता...32

नवाचार...33

सेवा कार्य..34

औचित्यहीन टैरिफ का जवाब है स्वदेशी

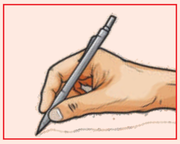

कोई भी शक्ति यदि भारत पर दवाब बनाकर शोषण आधारित असंतुलित व्यापारिक रिश्ते कायम करना चाहती है तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। ट्रम्प यह कैसे भूल सकते हैं कि यदि अमेरिका आज की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत 140 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया का विशालतम राष्ट्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र और कल की आर्थिक महाशक्ति है। भारत, अमेरिका सहित पूरी दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते चाहता है बशर्ते वो बराबरी और विश्वास की नींव पर खड़े हों। भारत के 280 करोड़ हाथ स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का दीप जलाने के लिए संकल्पित हैं।

भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कुछ उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है। अमेरिका 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की प्रतिक्रिया स्वरूप अर्थदंड के रूप में लगा रहा है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के हालिया निर्णयों की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि यह कदम अमेरिका से ज्यादा ट्रम्प की अस्थिर सोच का परिणाम अधिक है। भारत ही नहीं दुनिया का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि ट्रम्प सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं अपितु मात्र एक व्यापारी बन कर रह गए हैं और वह भी अदूरदर्शिता से पूर्ण। भारतीयों की दृष्टि में दवाब के ये दांव-पेच भारत की सार्वभौमिकता और स्वाभिमान को चुनौती हैं। कोई भी शक्ति यदि भारत पर दवाब बनाकर शोषण आधारित असंतुलित व्यापारिक रिश्ते कायम करना चाहती है तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। ट्रम्प यह कैसे भूल सकते हैं कि यदि अमेरिका आज की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत 140 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया का विशालतम राष्ट्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र और कल की आर्थिक महाशक्ति है। भारत, अमेरिका सहित पूरी दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते चाहता है बशर्ते वो बराबरी और विश्वास की नींव पर खड़े हों। भारत के 280 करोड़ हाथ स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का दीप जलाने के लिए संकल्पित हैं।

ट्रम्प द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही भारत के लिए उनके बदलते स्वरों की बानगी मिलने लगी थी जैसे, कश्मीर पर मध्यस्थता का राग अलापना, स्वयं को भारत-पाक संघर्ष विराम का सूत्रधार बताना, बांग्लादेश में भारत समर्थित लोकतान्त्रिक सरकार को अपदस्थ कर इशारे पर नाचने वाली सरकार स्थापित करना, वर्ल्ड ट्रेड टावर की आतंकी घटना में 3000 लोगों की हत्या के दोषी ओसामा बिन लादेन की शरणस्थली पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट-हाउस में आमंत्रित कर आतंक के केंद्र पाकिस्तान और आतंक के योद्धा भारत को एक तराजू में तोलने का प्रयास करना आदि। ट्रम्प ने दुनिया में लोकतंत्र के रक्षक का चोला पहने अमेरिका का नकाब उतार कर यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र के बारे में उनकी सोच सिर्फ, 'बातें हैं बातों का क्या' तक सीमित है, वास्तविक है तो केवल व्यापार।

भारत पर मनमर्जी थोपने की फिराक में बैठे ट्रम्प उसकी क्षमता को कम आँकने की भूल कर रहे हैं। बढ़े अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा, आभूषण, चमड़ा जैसे उद्योगों के ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसानों, मछुआरों और छोटे उद्योगों के साथ कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि इससे छोटे किसानों और व्यापारियों की जीविका प्रभावित होगी। ऐसे में व्यापारियों को जीएसटी में छूट तथा कम ब्याज पर ऋण देने जैसे कदम भारत सरकार को उठाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते टैरिफ का मुकाबला करने के लिए जन-जन से स्वदेशी तथा वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाने का आह्वान किया है।

अमेरिका ने दवाब को और बढ़ाते हुए छटे दौर की वार्ता के लिए अपने दल की 25 अगस्त से होने वाली भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है। ऐसे में भारत को अमेरिका की मनमानी कार्यवाही को एक अवसर के रूप में लेना होगा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है अत: भारत को नए देशों के साथ निर्यात संबंध स्थापित करने ही होंगे। अमेरिका की औचित्यहीन कार्यवाही विकसित भारत की यात्रा में उत्प्रेरक का कार्य करेगी। आज हम भारतीयों को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलने की शपथ लेनी होगी। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, "तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ"। ■

100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में संघ का विचार जन-जन तक पहुंचे। संघ को लेकर सुनी-सुनाई बातों से नहीं बल्कि संघ के चिंतन और संघ के विचार को तथ्यपरक रूप से जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 26 से 28 अगस्त 2025 तक '100 वर्ष की संघ यात्रा - नए क्षितिज' विषय पर तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। जिसमें सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने संघ के विचार, कार्य पद्धति और भारत की विचार दृष्टि को उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष रखा। प्रस्तुत हैं व्याख्यानमाला के मुख्य अंश:-

व्याख्यानमाला का प्रथम दिवस - 26 अगस्त 2025 : इस तीन दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन पूज्य सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने सेवानिवृत न्यायाधीश, पूर्व राजनयिक, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न देशों के राजनयिक, मीडिया संस्थानों के प्रमुख, पूर्व सेनाधिकारी और खेल व कला क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि संघ का निर्माण भारत को केंद्र में रखकर हुआ है और इसकी सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है। संघ कार्य की प्रेरणा संघ प्रार्थना के अंत में कही जाने वाली पंक्ति "भारत माता की जय" से मिलती है। संघ के उत्थान की प्रक्रिया धीमी और लंबी रही है, जो आज भी निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि संघ भले हिन्दू शब्द का उपयोग करता है, लेकिन उसका मर्म 'वसुधैव कुटुंबकम' है। इसी क्रमिक विकास के तहत गांव, समाज और राष्ट्र को संघ अपना मानता है। संघ कार्य पूरी तरह स्वयंसेवकों द्वारा संचालित होता है। कार्यकर्ता स्वयं नए कार्यकर्ता तैयार करते हैं।

व्याख्यानमाला के उद्देश्य पर उन्होंने कहा कि संगठन ने विचार किया कि समाज में संघ के बारे में सत्य और सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार का आयोजन हुआ था। इस बार चार स्थानों

पर कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक संघ का सही स्वरूप पहुँच सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की परिभाषा सत्ता पर आधारित नहीं है। हम परतंत्र थे, तब भी राष्ट्र था। अंग्रेजी का 'नेशन' शब्द 'स्टेट' से जुड़ा है, जबकि भारतीय राष्ट्र की अवधारणा सत्ता से जुड़ी नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद देश में उपजी विचारधाराओं के विकास पर उन्होंने कहा कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन उससे नई चेतना जागी। चिंतन हुआ कि आखिर कुछ मुट्ठीभर लोग हमें कैसे हरा सके? एक विचार यह भी उभरा कि भारतीयों में राजनीतिक समझ की कमी है। इसी आवश्यकता से कांग्रेस का उदय हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह वैचारिक प्रबोधन का कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकी। यह दोषारोपण नहीं, बल्कि तथ्य है। आजादी के बाद एक धारा ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया, वहीं दूसरी धारा ने अपने मूल की ओर लौटने की बात रखी। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने इस विचार को ही आगे बढ़ाया था।

उन्होंने संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर जी और अन्य महापुरुषों का मानना था कि समाज के दुर्गुणों को दूर किए बिना सब प्रयास अधूरे रहेंगे। बार-बार गुलामी का शिकार होना इस बात का संकेत है कि समाज में गहरे दोष हैं। डॉ. हेडगेवार जी ने ठाना कि जब दूसरों के पास समय नहीं है, तो वे स्वयं इस दिशा में काम करेंगे। 1925 में

संघ की स्थापना कर उन्होंने संपूर्ण हिन्दू समाज के संगठन का उद्देश्य सामने रखा।

हिन्दू नाम का मर्म समझाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हिन्दू' शब्द का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। यह नाम दूसरों ने दिया, पर हम अपने को हमेशा मानवशास्त्रीय दृष्टि से देखते आये हैं। हम मानते हैं कि मनुष्य, मानवता और सृष्टि आपस में जुड़े हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। हिन्दू का अर्थ है समावेश और समावेश की कोई सीमा नहीं होती। हिन्दू को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो इसमें विश्वास करता है कि अपने अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को बदलो मत। दूसरे की श्रद्धा का भी सम्मान करो, अपमान मत करो, ये परंपरा जिनकी है, संस्कृति जिनकी है, वो हिन्दू हैं। हमें संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन करना है। हिन्दू कहने से यह अर्थ नहीं है कि हिन्दू वर्सेस ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 'हिन्दू' का अर्थ है समावेशी।

उन्होंने कहा कि भारत का स्वभाव समन्वय का है, संघर्ष का नहीं है। भारत की एकता का रहस्य उसके भूगोल, संसाधनों और आत्मचिंतन की परंपरा में है। हमने बाहर देखने के बजाय भीतर झाँककर सत्य को तलाशा। इसी दृष्टि ने हमें सिखाया कि सबमें एक ही तत्व है, भले ही वह अलग-अलग रूपों में दिखता हो। यही कारण है कि भारत माता और पूर्वज हमारे लिए पूजनीय हैं।

भारत माता और अपने पूर्वजों को मानने वाला ही सच्चा हिन्दू है। कुछ लोग खुद को हिन्दू मानते हैं, कुछ भारतीय या सनातनी कहते हैं। शब्द बदल सकते हैं, लेकिन इनके पीछे भक्ति और श्रद्धा की भावना निहित है। भारत की परंपरा और डीएनए सभी को जोड़ता है। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे वे लोग भी स्वयं को हिन्दू कहने लगे हैं, जो पहले इससे दूरी रखते थे। क्योंकि जब जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है तो लोग मूल की ओर लौटते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिन्दू ही कहो। आप हिन्दू हो, ये हम बताते हैं। इन शब्दों के पीछे शब्दार्थ नहीं है, कंटेंट है, उस कंटेंट में भारत माता की भक्ति है, पूर्वजों की परंपरा है। 40 हजार वर्ष पूर्व से भारत के लोगों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि जो अपने आपको हिन्दू कह रहे हैं, उनका जीवन अच्छा बनाओ। जो नहीं कहते वो भी कहने लगेंगे। जो किसी कारण भूल गये, उनको भी याद आयेगा। लेकिन करना क्या है? संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन। जब हम हिन्दू राष्ट्र कहते हैं तो किसी को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। संघ किसी विरोध में और प्रतिक्रिया के लिए नहीं निकला है। हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है।

संघ कार्य पद्धति के विषय में उन्होंने कहा कि समाज उत्थान के लिए संघ दो मार्ग अपनाता है - पहला, मनुष्यों का विकास करना और दूसरा उन्हीं से आगे समाज कार्य कराना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है। संगठन का कार्य मनुष्य निर्माण का कार्य करना है। संघ के स्वयंसेवक विविध क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन संगठन उन्हें नियंत्रित नहीं करता। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर विरोध भी हुआ और संघ की उपेक्षा भी रही। लेकिन संघ ने समाज को अपना ही माना। शुद्ध सात्विक प्रेम ही संघ कार्य का आधार है।

संघ की विशेषता है कि यह बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत समर्पण पर चलता है। संघ सम्पूर्ण स्वावलंबी संगठन है। 'गुरु दक्षिणा' संघ की कार्यपद्धति का अभिन्न हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक स्वयंसेवक संगठन के प्रति अपनी आस्था और प्रतिबद्धता प्रकट करता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। हमारा प्रयास होता है कि विचार, संस्कार और आचार ठीक रहे। इतनी हमें स्वयंसवेक की चिंता करनी है, संगठन की चिंता वो करते हैं। हम सबको मिलकर भारत में गुट नहीं बनाना है। सबको संगठित करना है। विश्व में आस्था, पंथ सम्प्रदाय अनेक प्रकार के हैं, सबके मार्ग सही हैं और सभी एक ही जगह ले जाने वाले हैं।

व्याख्यानमाला का द्वितीय दिवस- 27 अगस्त 2025 : व्याख्यानमाला के द्वितीय दिवस पूज्य सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने उपस्थित बौद्धिक वर्ग को संबोधित करते हुए भारत के मार्ग और दुनिया में भारत की उपादेयता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा धर्म केन्द्रित है और धर्म आज दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा भारत को दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा और ऐसा समाज विकसित करना होगा जिसका दुनिया अनुकरण कर सके। इसके लिए सम्पूर्ण समाज का परिवर्तन करना होगा और इसकी शुरुआत घर से करनी होगी। इसके लिए संघ ने पंच परिवर्तन बताए हैं - कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व-बोध (स्वदेशी) और नागरिक कर्तव्यों का पालन। भारत को अपने स्व के आधार पर आत्मनिर्भर होना होगा जिसके लिए उन्होंने स्वदेशी को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। उन्होंने आज फिर से दोहराया कि संघ का कार्य शुद्ध सात्विक प्रेम और समाजनिष्ठा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि, संघ का स्वयंसेवक कोई व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ इंसेंटिव नहीं हैं, बल्कि डिसइंसेंटिव अधिक हैं। स्वयंसेवक समाज-कार्य में आनंद का अनुभव करते हुए कार्य करते हैं। संघ में आपको कुछ मिलेगा नहीं बल्कि जो आपके पास है वह भी चला जाएगा। यह हिम्मत वालों का काम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन की सार्थकता और मुक्ति की अनुभूति इसी सेवा से होती है। सज्जनों से मैत्री करना, दुष्टों की उपेक्षा करना, कोई अच्छा करता है तो आनंद प्रकट करना, दुर्जनों पर भी करुणा करना - यह चार बातें संघ का जीवन मूल्य है। हिन्दुत्व की मूल भावना पर उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व सत्य, प्रेम और अपनापन है। हमारे ऋषि-मुनियों ने हमें सिखाया कि जीवन अपने लिए नहीं है। यही कारण है कि भारत को दुनिया में बड़े भाई की तरह मार्ग दिखाने की भूमिका निभानी है। इसी से विश्व कल्याण का विचार जन्म लेता है। दुनिया की वर्तमान परिस्थिति पर

चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया कट्टरता, कलह और अशांति की ओर जा रही है। पिछले साढ़े तीन सौ वर्षों में उपभोगवादी और जड़वादी दृष्टि के कारण मानव जीवन की भद्रता क्षीण हुई है। उन्होंने गांधी जी के बताए सात सामाजिक पापों का विशेष उल्लेख किया जो हैं- परिश्रम रहित कर्म, विवेक रहित सुख, चरित्र रहित ज्ञान, नैतिकता रहित व्यापार, मानवता रहित विज्ञान, त्याग रहित धर्म और सिद्धांत रहित राजनीति। सम्पूर्ण विश्व इन सात पापों से त्रस्त है। इससे मुक्ति पाने के लिए दुनिया को अपना नजरिया बदलना होगा। दुनिया को धर्म का मार्ग अपनाना होगा। यह धर्म तत्व पूजा-पाठ और कर्मकांड से परे है। सभी प्रकार के रिलिजन से ऊपर है। धर्म हमें संतुलन सिखाता है, यह सिखाता है कि हमें भी जीना है, समाज को भी जीना है और प्रकृति को भी जीना है। धर्म ही मध्यम मार्ग है जो अतिवाद से बचाता है। धर्म का अर्थ है मर्यादा और संतुलन के साथ जीना। इस दृष्टिकोण से ही विश्व शांति स्थापित हो सकती है। धर्मयुक्त चिंतन में विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी के अस्तित्व को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बल दिया कि यही विश्व धर्म है और हिन्दू समाज को संगठित होकर इसे विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। वैश्विक संदर्भ में उन्होंने कहा कि शांति, पर्यावरण और आर्थिक असमानता पर चर्चा तो हो रही है, उपाय भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन समाधान दूर दिखाई देता है। इसके लिए प्रमाणिकता से सोचना होगा और जीवन में त्याग तथा बलिदान लाना होगा। संतुलित बुद्धि और धर्म दृष्टि का विकास करना होगा। उन्होंने भारत के मूल स्वभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि, हमने हमेशा अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए संयम रखा है। जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाया, उन्हें भी संकट में मदद दी है। व्यक्ति और राष्ट्रों के अहंकार से शत्रुता पैदा होती है, लेकिन हिन्दुस्तान अहंकार से परे है। उन्होंने कहा कि, आज समाज को संघ पर विश्वास है। संघ जो कहता है, उसे समाज सुनता है। यह विश्वास सेवा और समाजनिष्ठा से अर्जित हुआ है। अपने उद्‌बोधन में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से इस मातृभूमि को सींचा है, हम रहें या न रहें, भारत ये रहना चाहिए, हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भारत का रहना जरुरी है।

संघ कार्य की दृष्टि से भविष्य की दिशा पर सरसंघचालक जी ने कहा कि संघ का उद्देश्य है कि संघ कार्य सभी स्थानों, वर्गों और स्तरों पर पहुँचे। साथ ही समाज में अच्छा काम करने वाली सज्जन शक्ति आपस में जुड़े। इससे समाज स्वयं संघ की ही तरह चरित्र निर्माण और देशभक्ति के कार्य को करेगा। इसके लिए हमें समाज के कोने-कोने तक पहुंचना होगा। भौगोलिक दृष्टि से सभी स्थानों और समाज के सभी वर्गों एवं स्तरों में संघ की शाखा पहुंचानी होगी। सज्जन शक्ति से हम संपर्क करेंगे और उनका आपस में भी संपर्क कराएंगे। उन्होंने कहा कि संघ मानता है कि हमें समाज में सद्‌भावना लानी होगी और समाज के ओपिनियन मेकर्स से निरंतर मिलना होगा। इनके माध्यम से एक सोच विकसित करनी होगी। वे अपने समाज के लिए काम करें, उनमें हिन्दू समाज का अंग होने का अनुभव पैदा हो और वे भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी चुनौतियों का स्वयं समाधान ढूँढे। दुर्बल वर्गों के लिए काम करें। संघ ऐसा करके समाज के स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि, बाहर से आक्रामकता के कारण धार्मिक विचार भारत में आए। किसी कारण से कुछ लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। वे लोग यहीं के हैं, लेकिन विदेशी विचारधारा होने के कारण जो दूरियाँ बनीं, उन्हें मिटाने की जरूरत है। हमें दूसरे के दर्द को समझना होगा। एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र के अंग होने के नाते, विविधताओं के बावजूद, समान पूर्वजों और साझा सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ना होगा। यह सकारात्मकता और सद्‌भाव के लिए आवश्यक है। इसमें भी हम समझ-बूझकर एक-एक कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारत की आर्थिक दृष्टि पर उन्होंने कहा कि देश में छोटे-छोटे प्रयोग हुए हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिमान गढ़ना होगा। हमें एक ऐसा विकास मॉडल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और पर्यावरण का संतुलन हो। ताकि वे विश्व के लिए उदाहरण बने। पड़ोसी देशों से रिश्तों पर उन्होंने कहा कि नदियाँ, पहाड़ और लोग वही हैं, केवल नक्शे पर लकीरें खींची गई हैं। विरासत में मिले मूल्यों से सबकी प्रगति हो, इसके लिए उन्हें जोड़ना होगा। पंथ और संप्रदाय अलग हो सकते हैं, संस्कारों पर मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में परिवर्तन लाने से पहले हमें अपने घर से समाज परिवर्तन की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए संघ ने पंच परिवर्तन बताये हैं। यह हैं कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व की पहचान तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन। उन्होंने उदाहरण दिया कि पर्व-त्योहार पर पारंपरिक वेशभूषा पहनें, बाजार के खाने की अपेक्षा घर पर तैयार भोजन करें, दुनिया घूमने के साथ-साथ देश के स्थलों का भ्रमण करें, अपने आस-पास झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले भी अपने ही हैं उनके जीवन को भी देखें। घर में बोल-चाल में अपनी भाषा का प्रयोग करें, स्वभाषा में हस्ताक्षर करें और स्थानीय उत्पादों को सम्मानपूर्वक खरीदें।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे पूर्वज देश के लिए हंसते-हंसते फाँसी पर चढ़ गए, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम 24 घंटे देश के लिए जिएं। उन्होंने कहा कि, हमें हर हाल में संविधान और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई उकसावे की स्थिति हो तो न टायर जलाएँ, न हाथ से पत्थर फेंकें। उपद्रवी तत्व ऐसे कार्यों का लाभ उठाकर हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें कभी उकसावे में आकर अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों में भी देश और समाज का ध्यान रखकर अपना काम करना चाहिए। अंत में वह यह स्पष्ट करना भी नहीं भूले कि संघ क्रेडिट बुक में नहीं आना चाहता। संघ नहीं चाहता है कि लोग कहें संघ के कारण से परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि भारत ऐसी छलांग लगाए कि उसका कायापलट तो हो ही, पूरे विश्व में सुख और शांति कायम हो जाए। विश्व के कल्याण के लिए भारतीय समाज को उदाहरण बनकर स्वयं को प्रस्तुत करना होगा।

व्याख्यानमाला का तृतीय दिवस – 28 अगस्त 2025 (जिज्ञासा समाधान)

व्याख्यानमाला का तृतीय दिवस प्रश्नोत्तरी के रूप में जिज्ञासा समाधान को समर्पित रहा। इस अवसर पर पूज्य सरसंघचालक जी के द्वारा संघ के विषय में विभिन्न विषयों पर पूछे गये लगभग 218 जिज्ञासाओं के उत्तर के माध्यम से जन-सामान्य की जिज्ञासा का समाधान किया गया। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण सभी प्रश्न यहां नहीं लिए जा सकते हैं। प्रस्तुत हैं संक्षिप्त में प्रश्नोत्तरी के मुख्य अंशः-

तकनीक आधुनिकीकरण के युग में संस्कार, परम्पराओं के संरक्षण की चुनौती और शिक्षा प्रणाली में गुलामी की झलक को लेकर किये गये प्रश्न के उत्तर में सरसंघचालक जी ने कहा कि, तकनीकी और आधुनिकता का शिक्षा से विरोध नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है नई तकनीक आती है उसको आने से कोई रोक नहीं सकता, मनुष्य के भले के लिए उसे खोजा जाता है, उसका उपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य को तकनीक का मालिक बने रहना चाहिए, तकनीक मनुष्य का मालिक न बने। शिक्षा केवल स्कूलिंग या इनफार्मेशन देना नहीं है, मनुष्य सुसंस्कृत बने, मनुष्य वास्तविक मनुष्य बने इसको शिक्षा कहते हैं। ऐसी शिक्षा अपेक्षित है। हमारी शिक्षा पद्धति लुप्त कर दी गयी और ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की गयी जिससे आक्रामक शक्तियां इस देश पर राज्य कर सकें और हम गुलाम बने रहें। लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं इसलिए बच्चों को अतीत की जानकारी देनी चाहिए जिससे वे आत्मगौरव से भर सकें। नई शिक्षा नीति में इस दिशा में प्रयास चल रहा है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि अंग्रेजी नॉवेल पढ़ना बुरा नहीं लेकिन साथ ही प्रेमचंद को भी पढ़ें। भाषा की दृष्टि से अनेक भाषाओं को सीखना हमारे लिए अच्छा है किन्तु मातृभाषा का अच्छा ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलों में संस्कृत भाषा की अनिवार्यता न हो किन्तु भारत को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान जरुरी, इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए।

जनसंख्या असंतुलन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जन्म दर 3 होनी चाहिए उससे अधिक नहीं। देश विभाजन का संघ ने विरोध क्यों नहीं किया का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पहले गांधी जी की देश विभाजन के लिए असहमति थी, बाद में गांधी जी द्वारा विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद विभाजन रुक नहीं सका, संघ भी कुछ नहीं कर सका। भारत अखंड है यह एक सत्य है, जबरदस्ती उस सत्य को नकारकर चलने वाले नुकसान में हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन से सम्बंधित शेषाद्री जी की पुस्तक 'ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन' पढ़नी चाहिए। वर्ण व्यवस्था को लेकर किये गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जाति और वर्ण कभी व्यवस्था थी लेकिन आज अव्यवस्था बन चुकी है। वास्तव में शोषणमुक्त और समतायुक्त नई व्यवस्था आनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत शान्ति है, और होनी चाहिए किन्तु अन्य देश बुद्ध के देश नहीं हैं, युद्ध की भाषा बोलने वाले देशों के लिए शस्त्र जरुरी हैं। संघ की प्रार्थना में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई पराजित न कर सके ऐसी अजेय शक्ति दो। दूसरों को पराजित करने के लिए हमने शक्ति नहीं मांगी।

संघ समय के साथ बदलाव भी करता है। संघ के स्थिर विचार तीन हैं पहला व्यक्ति निर्माण से समाज के आचरण में परिवर्तन संभव है, दूसरा समाज को संगठित करने से बाकी परिवर्तन अपने आप होते हैं और तीसरा हिन्दुस्थान हिन्दू राष्ट्र है। इन तीन बातों को छोड़कर संघ में सब बदल सकता है। संघ की क्या योजना है? प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि संघ की कोई योजना नहीं होती, संघ के स्वयंसेवकों की योजना होती है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संघ के एक या एक से अधिक संगठन काम कर रहे हैं उनके द्वारा धीरे-धीरे व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। विदेशी धन भारत में आने को लेकर उन्होंने कहा कि सेवा के लिए आये तो कोई दिक्कत नहीं है किन्तु उसका उपयोग मतान्तरण के लिए होगा तो रोक लगनी चाहिए, यह सरकार का काम है। सरकारी अधिकार से मंदिरों की मुक्ति के सम्बन्ध में किये गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी मंदिर सरकारी अधिकार में नहीं हैं, कुछ निजी हैं तो कुछ ट्रस्ट के अधीन भी हैं। मंदिरों को भक्तों के संरक्षण में दिए जाने का वातावरण बन रहा है किन्तु इसके लिए भक्तों को भी मंदिरों की व्यवस्था संभालने का दृश्य खड़ा करना चाहिए। कई सरकारी, निजी और ट्रस्ट के मंदिर अच्छी व्यवस्था वाले भी हैं और इसका उल्टा भी है। खराब और भ्रष्ट व्यवस्था वाला यह चित्र बदलना चाहिए। मंदिर जब मिलेंगे उनकी व्यवस्था बनाने की रचना उस-उस पंथ सम्प्रदाय के अनुसार पूजन और मंदिर में आने वाले धन के उपयोग की व्यवस्था बननी चाहिए। वर्तमान समय में अमेरिका के द्वारा दिखाई जा रही दबंगई पर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य है, होना चाहिए, किन्तु मुक्त रूप से होना चाहिए किसी भी दबाव के अधीन नहीं। मित्रता दबाव से नहीं चलती है। हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनें किन्तु परस्पर निर्भरता से दुनिया चलती है। इसे कैसे करना है यह सरकार का विषय है। सरकार इस नाते से जो करेगी उसके हम समर्थन में रहेंगे। शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी को लेकर किये गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सरकार और प्राइवेट सेक्टर 30 प्रतिशत लोगों को रोजगार दे सकती है, इसलिए हमें उद्यमिता की ओर जाना चाहिए, हमें नौकर नहीं नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ऐसा करने वाले बड़े बनते हैं। परिश्रम करने वालों को सम्मान देना चाहिए। काम को छोटा बड़ा मानने से ही समाज में गिरावट आनी शुरू हुई। समाज में श्रम प्रतिष्ठा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। एक अन्य जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हिन्दवी, आर्य, भारतीय, हिन्दू शब्दों के झगडे में नहीं पड़ना चाहिए, संघ की दृष्टि में ये समानार्थक हैं। इनका कंटेंट देखना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर उन्होंने कहा कि शब्दों के कारण ही हिन्दू-मुस्लिम शब्द आ गये, जो एक ही हैं उनको एक क्या करना। रिलिजन बदलने से कौम नहीं बदल जाती है। हिन्दू-मुस्लिम होने से पहले हम भारतीय हैं। भारतीयों के लिए सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रकार सरसंघचालक जी ने अनेक जिज्ञासाओं का समाधान किया। ■

सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया का नाम संघ है

आज हमारे मध्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय क्षेत्र संघचालक, श्री सूर्य प्रकाश टोंक जी उपस्थित हैं। आप पूर्व में प्रांत संघचालक का दायित्व तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। वर्ष 2018 में आयोजित राष्ट्रोदय के सफल आयोजन में आपकी महती भूमिका रही है। प्रस्तुत हैं 'संघ जैसा मैने देखा' विषय पर मा. सूर्य प्रकाश टोंक जी से डॉ. नीलम कुमारी द्वारा लिए गए साक्षात्कार के मुख्य अंश-

सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके जीवन की विकास यात्रा के बारे में कि आप संघ के सम्पर्क में कैसे आये?

वैसे जीवन तो बहुत सामान्य है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं संघ के संपर्क में नहीं आया होता तो शायद जीवन में बदलाव न आता। संघ ने मुझे बहुत बदला। मुझे याद है मैं एक उदण्ड, मोहल्ले में खेलने वाला बालक था और संघ से परिचय संयोग से हुआ। 1963 में हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद क्रिकेट खेल रहा था, तभी मोहल्ले का एक लड़का मुझे शर्मा स्मारक के पीछे लगने वाली राम वाटिका शाखा में ले गया। मुझे पता नहीं था शाखा क्या होती है। वहां 25-30 विद्यार्थी खेल रहे थे, मैंने भी खेला और मेरे पाले की जीत हुई। स्थान नया था, खेल नया था, सब शालीनता से "भईय्या" कहकर संबोधित कर रहे थे। वहां गीत और प्रार्थना हुई। शाखा के विभाग कार्यवाह ने मेरा परिचय पूछा और बोले -"तुम बढ़िया खेलते हो, कल आओगे।" मैंने हां कर दी। इस प्रकार मेरा परिचय संघ से हुआ।

आपका संघ से जुड़ाव एक दीर्घ और समृद्ध यात्रा रहा है तथा आपने विभिन्न दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया है। ऐसे में, आपकी दृष्टि में 'संघ' क्या है?

मैं अगर अपने से उसकी कोई असेसमेंट करने का प्रयत्न करूं तो संघ एक अलग प्रकार का संगठन है। समाज में किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता और आज मैं जिस दायित्व पर हूं उसके बाद अगर मैं यह विचार करूं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी आवश्यकता राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, व्यक्तियों की दृष्टि से है, और संघ वहां नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने लंबे समय के अनुभव के बाद ये निश्चित रूप से आज कह सकता हूं कि संघ सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया का नाम है।

मा. सूर्य प्रकाश टोंक जी
क्षेत्र संघचालक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश

आपने बहुत सुंदर शब्दों में संघ को परिभाषित किया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा वो कौन सा मूल उद्देश्य था जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई?

संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूज्य डॉ. केशवराव बलीराम हेडगेवार जी ने की। उस समय न नाम निश्चित था, न कार्यप्रणाली और न ही दिशा स्पष्ट थी। केवल यह संकल्प था कि राष्ट्र को सशक्त और समाज को सबल बनाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। अगले पंद्रह वर्षों में डॉ. हेडगेवार ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रचिंतन और सक्रिय कार्य के लिए प्रेरित किया तथा हिंदू समाज को संगठित, सबल और सक्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया।

आप स्वयं एक सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं। आपके अनुभव में एक आदर्श स्वयंसेवक के व्यक्तित्व में कौन-कौन से गुण निहित होने चाहिए?

कहा जाता है कि यदि संघ को जानना है तो उसकी शाखा में आइए। वास्तव में संघ स्वयं कुछ नहीं करता, बल्कि उसके स्वयंसेवक ही सब कुछ करते हैं। संघ का उद्देश्य व्यक्ति के मन को राष्ट्रोन्मुख बनाना है और उसकी सभी गतिविधियां, क्रियाकलाप तथा प्रक्रियाएं शाखा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती हैं। शाखा में तैयार हुआ स्वयंसेवक अत्यंत व्यवस्थित, अनुशासित तथा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होता है- यही एक आदर्श स्वयंसेवक के मूल गुण हैं।

एक स्वयंसेवक की प्रगति किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि संघ

की विशेष पद्धति का फल है। आप अपने अनुभव से बताएं कि वह पद्धति क्या है और कैसे कार्य करती है?

जब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था और स्वयंसेवक बना, तब मेरी यात्रा में दो व्यक्तियों ने विशेष भूमिका निभाई। एक गणित के गोल्ड मेडलिस्ट और नगर कार्यवाह प्रो. विनोद अग्रवाल थे, जो बाद में मेरठ के डीएन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य बने। कुछ दिनों तक मैं शाखा नहीं गया तो वे स्वयं मेरे घर आए, हालचाल पूछा और गणित पढ़ाने के लिए अपने घर बुलाया। उन्होंने न केवल कठिन विषय को सरलता से समझाया बल्कि आत्मीयता से चाय भी पिलाई। इसी प्रकार नरेश जी, जो बाद में खड़गपुर आईआईटी में प्रोफेसर रहे, उन्होंने भी मेरे जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में संघ अपने किसी स्वयंसेवक को कभी छोड़ता नहीं, बल्कि उसे सँभालने, जोड़ने और संवारने का कार्य करता है- यही उसकी अनूठी कार्यपद्धति है।

आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले सेवा में जुटते नजर आते हैं। आप स्वयं इस भूमिका को किस रूप में देखते हैं?

1963 में स्वयंसेवक के रूप में मेरी यात्रा शुरू हुई और मात्र दो वर्ष बाद 1965 का युद्ध आ गया। उस समय भी शाखा ने हम सबमें यह संस्कार भरे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। चाहे रात के 12 बजे पार्क में इकट्ठा होना हो या कठिन परिस्थितियों में अनुशासन बनाए रखना हर स्वयंसेवक का मन देश के लिए प्राण अर्पित करने को तत्पर रहता था। यही संघ और स्वयंसेवकों की विशेषता है कि किसी भी आपातकाल में वे निःस्वार्थ भाव से सेवा और समर्पण के साथ खड़े दिखाई देते हैं।

आपके जीवन का ऐसा कोई विशेष स्मरण या अनुभव, जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?

हालांकि आज सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने दिशा देने का काम किया। एक बार मैं कार्यवाह के नाते दायित्व निभा रहा था। यह घटना राम मंदिर आंदोलन से ठीक पहले की है। उस समय हम 10-12 कार्यकर्ता किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। विचारों में मतभेद था और मेरी राय बहुमत से अलग थी। अचानक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाराज होकर अपनी डायरी उठाई और कहा - 'जो तुम्हें ठीक लगे, वही करो' और बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। मुझे यह बात गहरे तक लगी और लगा कि यह मेरा अपमान है। उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब मैं शाखा नहीं जाऊँगा।

कुछ दिन बाद अधीश जी, जो प्रचार विभाग से जुड़े थे और मेरठ कार्यालय में रहते थे, उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने मुझसे बात की और कहा - 'ऐसे संगठन में मतभेद तो होंगे ही, लेकिन व्यक्तिगत आहत होकर अलग होना उचित नहीं है।' उन्होंने लगभग ढाई घंटे तक मुझसे धैर्यपूर्वक चर्चा की और मेरे भीतर जो भावनात्मक गाँठ बन गई थी, उसे खोल दिया। अंत में उन्होंने मुझे मनाया और कहा- 'ठीक है, अब नेकर पहनकर स्कूटर निकालो, हम साथ चलते हैं।'

उसके बाद लगातार पांच-छह दिन तक वे मुझे स्वयं शाखा लेकर गए। वहां सारी प्रक्रिया मेरे साथ की, ताकि मैं सहज हो सकूँ। उनके इस व्यक्तिगत प्रयास ने मुझे दोबारा संघ से जोड़ा। यह उनके जीवन में निभाई गई अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक अनुषांगिक संगठन विभिन्न उद्देश्यों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ऐसे में संघ में प्रचार विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी?

मैंने गुरुजी को 1973 तक सत्संग चालक के रूप में कार्य करते हुए देखा है। 1967 में जब मैं लखनऊ में प्रथम वर्ष का छात्र था, तब उनके तीन बौद्धिक मेरे सामने हुए। उस समय बाबा साहब आपटे भी एक प्रचारक के रूप में उपस्थित थे। मुझे गुरुजी और आपटे जी से थोड़ी-बहुत बातचीत का अवसर मिला। उस बातचीत से मैंने महसूस किया कि संघ के लिए प्रचार या अखबारों में समाचार छपना कोई लक्ष्य नहीं था। स्वयंसेवक तो समाचार पत्रों और फोटोग्राफी से दूर ही रहते थे।

लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं। आज समाज और राष्ट्रीय जीवन में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है। तेजी से सूचना प्रसारित करने के लिए सही साधन जरूरी हो गए हैं। स्वयंसेवकों और समाज तक संघ के विचार स्पष्ट पहुंचें, इसके लिए पत्र-पत्रिकाएं और बाद में मीडिया का सहारा लिया गया। प्रारंभ में छोटी-छोटी 'जागरण पत्रिकाएं' इसी उद्देश्य से निकाली गईं।

आप 'प्रेरणा विचार' के माध्यम से हमारे दर्शकों और पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

संघ अपने शताब्दी वर्ष (3 अक्टूबर 2025 से 12 अक्टूबर 2026) को समाज और राष्ट्र के उत्थान हेतु विशेष कार्यक्रमों के रूप में मनाने जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समाज और संघ एकरूप होकर राष्ट्र जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं सभी स्वयंसेवकों से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर वे अपने जीवन में कम-से-कम एक कार्य ऐसा निश्चित करें जो राष्ट्रहित में हो। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर समाज और परिवार में इस भावना से कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र निर्माण का कार्य आगे बढ़ता जाएगा। ■

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020
पांच वर्षों की यात्रा और प्रासंगिकता

प्रणय कुमार
शिक्षाविद एवं संस्थापक,
सामाजिक संगठन शिक्षा-सोपान

29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को लागू हुए अब पाँच वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में तथा 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की अध्यक्षता में शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 का प्रारूप अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया और देशभर में व्यापक विचार-विमर्श व जनभागीदारी के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। 2014 से जून 2020 के बीच लगभग दो लाख ग्राम पंचायतों, छह हजार प्रखंडों एवं नगरीय निकायों और 676 से अधिक जिलों से सुझाव प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप एक व्यापक, संतुलित और दूरदर्शी शिक्षा नीति तैयार हुई। जहाँ पूर्ववर्ती नीतियाँ मुख्यत: शिक्षा में अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित थीं, वहीं 2020 की नीति का दृष्टिकोण कहीं अधिक व्यापक और बहुआयामी है। इसका उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देने वाली शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़कर शोध, नवाचार, कौशल, सहयोग, समावेशन और आत्मनिर्भरता के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के द्वारा देखे गए विकसित भारत के स्वप्नों को साकार करने वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है। यह नीति शिक्षा के मायने को ही पुनर्परिभाषित करती है और आजीवन अध्ययन व अधिगम को इसके केंद्र में रखती है।

दशकों तक भारत में विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना एक बड़ी चुनौती रही है। अनेक बच्चे अर्थाभाव या अन्य कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश होते रहे हैं। इस नीति ने इस चुनौती का सीधा समाधान प्रस्तुत किया है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक सभी बच्चों को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 10 तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, और अब तक सात चरणों में देशभर में 14,500 पीएम श्री विद्यालय लोकार्पित किए जा चुके हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है कि 2027 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणना जैसे आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल कर लें। गैर-सरकारी संगठन 'असर' तथा एनसीईआरटी के पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा अब 'परख' द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में नामांकन, उपस्थिति, अक्षर और शब्द पहचान, पढ़ने-लिखने की क्षमता, संख्यात्मक और गणितीय कौशल तथा प्रारंभिक शिक्षा वर्षों में समग्र अधिगम परिणामों में 60 से 64 प्रतिशत सुधार दर्ज किया गया है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को रोचक और व्यावहारिक बनाने के लिए फाउंडेशनल स्टेज (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं) हेतु "जादुई पिटारा" विकसित किया गया है, जो खेल-खेल में सीखने पर बल देता है। इस किट में कार्ड, कहानियाँ और ऑडियो-विजुअल सामग्री सम्मिलित है, जिससे शिक्षण आनंददायक और सहभागितापूर्ण बन सके। विशेष रूप से, इसे केवल मुद्रित पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में ई-प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

भारत में लंबे समय से कौशल-आधारित शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह पहली नीति है जिसने औपचारिक रूप से कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में व्यावहारिक, तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों को जोड़ा

है। विद्यालयी छात्रों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में देशभर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जा चुके हैं, और मौजूदा बजट में इस संख्या को 50,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति की एक और प्रमुख विशेषता डिजिटल संसाधनों का व्यापक उपयोग है। सीबीएसई, एनसीईआरटी और यूजीसी ने पीएम ई-विद्या, दीक्षा, विद्या समीक्षा केंद्र, ई-पाठशाला, स्वयं, स्वयं प्रभा, समर्थ, निष्ठा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी जैसे पोर्टल्स एवं ई-मंचों के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। अब ये संसाधन दूरस्थ गाँवों के बच्चों और शिक्षकों के लिए भी सुलभ हैं। इस नीति में शिक्षक-प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और मूल्यांकन पर भी विशेष बल दिया गया है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (एनपीएसटी) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि छात्रों के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

भाषाई स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को अनिवार्य और कक्षा 8 तक वैकल्पिक रूप से जारी रखने को प्राथमिकता देती है। इसके साथ ही यह भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, कला और संस्कृति को पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण और संवर्धन भारत की भाषाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं है। इसी दिशा में एनसीईआरटी ने मातृभाषा और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अब तक भारत की लगभग 117 भाषाओं में अध्ययन-सामग्री तैयार की जा चुकी है। 14 भाषाओं में 1,000 से अधिक कहानियाँ ई-पाठशाला मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक और भाषाई परिवेश के अनुरूप सीख सकें। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट में महत्वाकांक्षी "भारतीय भाषा परियोजना" की घोषणा की है। यह योजना न केवल भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास को गति देगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भाषाई विरासत को भी प्रदर्शित करेगी। भारत में प्रचलित सभी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं; उनमें भले ही शैलीगत विविधता हो, परंतु भाव, विचार एवं तत्त्व-चिंतन के स्तर पर उनमें अद्भुत एकता एवं साम्यता है। इतनी कि सहसा उसे देख एवं अनुभूत कर देश व दुनिया के लोग विस्मित एवं चमत्कृत हो उठते हैं। इस प्रकार भारतीय भाषाओं का संवर्धन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की इस अपेक्षा को भी पूरा करता है कि वैश्विक भाषाई विविधता का संरक्षण और संवर्धन किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक, विद्यालयी शिक्षा की संरचना में व्यापक सुधार है। दशकों पुराने 10+2 ढाँचे को बदलकर 5+3+3+4 ढाँचा लागू किया गया है, जिसमें आधारभूत स्तर (पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 2 तक), प्रारंभिक स्तर (कक्षा 3 से 5), मध्य स्तर (कक्षा 6 से 8) तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) शामिल हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकें पहले ही युगीन आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रकाशित की जा चुकी हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 की पुस्तकें इस वर्ष और अगले वर्ष पूरी हो जाएँगी। इस पाठ्यक्रम में भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विचारों व आवश्यकताओं का समावेश है।

विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक लचीलापन और बहुविषयकता को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) लागू किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा, खेल-कूद, पाठ सहगामी गतिविधियों तथा कौशल के लिए क्रेडिट अंक प्रदान किए जाते हैं। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, तो अर्जित क्रेडिट उसके खाते में सुरक्षित रहते हैं और वह आगे पुनः अध्ययन कर और क्रेडिट जोड़ सकता है। यहाँ तक कि सीखने या कौशल अर्जन के लिए प्रति घंटा यानी निर्दिष्ट अवधि के आधार पर भी क्रेडिट प्राप्त करने की व्यवस्था है। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई ने घोषणा की है कि सत्र 2025-26 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। एनसीईआरटी ने परख (परफॉर्मेंस एसेसमेंट, रिव्यू, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट) नामक एक व्यापक रिपोर्ट कार्ड प्रारंभ किया है, जो केवल अंकों तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों, नैतिकता, सृजनात्मकता, सहयोग, संवेदनशीलता और अन्य गुणों का आकलन करेगा। इसी प्रकार, चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम में बहु-प्रवेश (मल्टीपल एंट्री) और बहु-निकास (मल्टीपल एग्जिट) की सुविधा दी गई है, जिससे विद्यार्थियों का समय, धन और परिश्रम व्यर्थ न जाए। एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर प्रमाणपत्र, दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर ऑनर्स डिग्री और चार वर्ष पर शोध सहित ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद सीधे इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा स्टेम शिक्षा में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएनआरएफ) योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यह नीति दुहरी (ड्वेल) डिग्री और बहुविषयक अध्ययन को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे किसी भी संकाय (स्ट्रीम) के विद्यार्थी अपनी रुचि, पात्रता और आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा के विषय चुन सकते हैं।

शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत के लिए नया विचार नहीं है। प्राचीन काल में

नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी और पुष्पगिरि जैसे विश्वविद्यालय वैश्विक ज्ञान-केन्द्र थे, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी, शोधार्थी और दार्शनिक आते थे। आज उसी गौरवशाली परंपरा और आदर्श को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान न केवल विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी अपने परिसरों की स्थापना कर रहे हैं। इसी प्रकार, विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में अकादमिक केन्द्र खोल रहे हैं, जिससे वैश्विक ज्ञान-साझाकरण की परिकल्पना को ठोस रूप मिल रहा है। इस दिशा में आईआईटी मद्रास ने ज़ांज़ीबार में, आईआईटी दिल्ली ने आबू धाबी में, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएफटी ने दुबई में परिसर खोले हैं, जबकि आईआईटी मुंबई ने तोहोकू विश्वविद्यालय (जापान) के साथ एक संयुक्त अकादमिक केंद्र स्थापित किया है। दूसरी ओर, विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में सक्रिय हो रहे हैं-गुजरात के गिफ्ट सिटी में 2, गुरुग्राम में एक और बेंगलुरु में एक परिसरों की स्थापना हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इटली के कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने भारत में शिक्षा केन्द्र खोलने में रुचि दिखाई है, और 11 विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किए गए हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ एबर्डीन; ऑस्ट्रेलिया के डीकन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वूलॉन्गॉन्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया; अमेरिका के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी; तथा इटली के इस्तितुतो यूरोपियो दी डिजाइन शामिल हैं। कुल मिलाकर, शीर्ष 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के प्रारंभिक चरण को पार कर चुके हैं और 5 और अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं। इन विश्वविद्यालयों का आगमन विद्यार्थियों को देश में रहते हुए विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराएगा, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, अकादमिक गुणवत्ता को नए आयाम पर ले जाएगा और ज्ञान-केंद्रित परिसर व समृद्ध शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सहायक होगा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इससे विद्यार्थियों की विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी, आर्थिक बोझ घटेगा, और भारत को पुनः एक वैश्विक ज्ञान-केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा, जिसका विश्वभर में सम्मान और मान्यता होगी।

हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार केवल कागजी योजनाओं तक सीमित न रहकर ठोस परिणामों में परिवर्तित हुए हैं। वर्ष 2014-15 में केवल 11 भारतीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में स्थान प्राप्त कर सके थे। वर्ष 2025-26 तक यह संख्या बढ़कर 54 हो गई है। भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन के साथ इस सूची के शीर्ष चार देशों में स्थान बना लिया है। इन रैंकिंग्स के लिए उपयोग किए जाने वाले 10 वैश्विक मानकों में से कई पर भारतीय विश्वविद्यालय अब शीर्ष 100 में गिने जाते हैं। यह बदलाव केवल आँकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास में भी उछाल है। नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। देश में अब लगभग 1,76,000 पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 118 से अधिक यूनिकॉर्न्स शामिल हैं, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। पेटेंट दाखिल करने के क्षेत्र में भी भारत ने नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। वर्ष 2023-24 में 92,168 पेटेंट आवेदन के साथ भारत विश्व के शीर्ष छह देशों में शामिल हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वर्ष 2024 में 81वें स्थान से 2025 में 39वें स्थान पर पहुँचना और वैश्विक फिनटेक अपनाने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत अब केवल अतीत के सपनों का पीछा नहीं कर रहा, बल्कि नए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।

केवल पाँच वर्षों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था में नई दृष्टि, नयी ऊर्जा और नया आत्मविश्वास भर दिया है। संरचनात्मक सुधार लागू हो चुके हैं, नए पाठ्यपुस्तक और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हैं, और नामांकन ही नहीं, अधिगम परिणामों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 में 3.4 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है। यह वृद्धि केवल संख्या नहीं, बल्कि अवसरों के विस्तार का प्रतीक भी है। फिर भी, आगे की राह आसान नहीं होगी। सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो) के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का विस्तार, प्रशिक्षित मानव पूंजी का विकास और ठोस कार्ययोजना आवश्यक होगी। डिजिटल खाई को पाटना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करना और शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार आगामी वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कक्षा 9-10 में दो भारतीय भाषाएँ और एक विदेशी भाषा, तथा कक्षा 11-12 में एक भारतीय और एक विदेशी भाषा पढ़ाने का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश, यह प्रावधान अब तक व्यवहार में लागू नहीं हुआ है। समाज और सरकार दोनों को यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा केवल संचार, संप्रेषण और ज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता की जीवंत धरोहर है।

समग्र रूप से देखा जाए तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 केवल एक सरकारी योजना या दृष्टिपत्र नहीं है, बल्कि यह भारत को ज्ञान-आधारित, आत्मनिर्भर वैश्विक नेतृत्व की दिशा में मार्गदर्शित करने वाला एक व्यापक रोडमैप है। इसकी उपलब्धियाँ आत्मविश्वास जगाती हैं, परंतु इसके अंतिम लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आने वाला दशक निर्णायक होगा। यदि इस नीति के प्रावधानों को पूर्ण निष्ठा, दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और निरंतरता के साथ लागू किया गया, तो यह निस्संदेह 21वीं सदी में शिक्षा के माध्यम से भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाला ऐतिहासिक परिवर्तन सिद्ध हो सकता है। ■

अमृत काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता

भर्तृहरि महताब'
उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

अमृत काल : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : 'अमृत काल' शब्द का प्रयोग पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्तूबर, 2021 में किया गया था। आजादी के 75 वर्ष के आगे के 25 वर्षों अर्थात् 2047 तक के काल को उनके द्वारा भारत के उत्थान के 'अमृत काल' के रूप में निरूपित किया गया था। इस अमृत काल के दौरान भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित भारत बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किया गया है।

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में घोषित 'अमृत काल' न केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का भी स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करता है। इस काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता, उनका विकास, परस्पर संवाद और सांस्कृतिक समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है कोई भी राष्ट्र बिना भाषाओं के उत्थान एवं विकास के अपने आप को विकसित राष्ट्र नहीं कह सकता। आज रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस इत्यादि जितने भी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं सबकी भाषाएँ न केवल विकसित हैं बल्कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र की भाषा होने का दर्जा भी प्राप्त है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत 'अमृत काल' की अवधारणा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण की दिशा में नए संकल्प और दृष्टिकोण को अपनाना है। यह काल भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य और सभ्यता के पुनर्निर्माण एवं विकास का प्रतीक है।

हिंदी भाषा का विकास : हिंदी भाषा का विकास आदिकालीन प्राचीन संस्कृत से हुआ है, जो मध्यकाल में प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से विकसित हुई 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखा गया, जिसमें संतों ने हिंदी में रचनाएँ की। तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा बाई जैसे संतों ने हिंदी को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद रीतिकाल के कवियों ने हिंदी भाषा को अलंकारों से सुसज्जित किया। उन्होंने दिखाया कि भाषा में अलंकारों के माध्यम से न केवल सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया जा सकता है बल्कि उनसे भाषा का श्रृंगार भी किया जा सकता है।

हिंदी भाषा के साथ अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता और योगदान : भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत और अंग्रेजी प्रमुख हैं। इन भाषाओं का साहित्य, संस्कृति और इतिहास भारतीय समाज की विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। अमृत काल में इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में हिंदी भाषा के अलावा बांग्ला भाषा और तमिल भाषा में साहित्य सृजन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता के क्षेत्र-

शिक्षा : सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस नई शिक्षा नीति का मूल ही इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। इससे न केवल अन्य भारतीय भाषाओं का विकास होगा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास तेजी से होगा। यह सार्वभौम सत्य है कि प्रत्येक बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखता है जो नैसर्गिक रूप में उसे अपनी माता से विरासत में मिलती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही हैं। इससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो उनके मानसिक विकास और सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा।

प्रशासन : हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के बाद इसे संविधान में व्यवस्था करके मूर्त रूप प्रदान किया गया। अनुच्छेद 351 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो संघ सरकार को हिंदी भाषा का विकास करने के लिए निर्देश देता है। इस अनुच्छेद में संघ सरकार द्वारा हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कर्तव्य निर्धारित

किए गए हैं जिससे वह भारत की सांस्कृतिक एकता और समृद्धि का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 351 में उल्लेख है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि सुनिश्चित करे। सरकार द्वारा अमृत काल में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे प्रत्येक भाषा-भाषी राजभाषा से भी अपनी निकटता महसूस करे सरकारी दस्तावेज, आदेश, सूचनाएँ और वेबसाइट राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

साहित्य और संस्कृति : हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को उजागर किया है। अमृत काल में सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जा रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति और साहित्य को वैश्विक मंच पर संपूर्ण पहचान मिल सके। इसके लिए अमृत काल में सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही।

मीडिया और संचार में सभी भारतीय भाषाओं की भागीदारी : हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन चैनलों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार के ज्ञान का आदान-प्रदान तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। यूनिकोड के आविर्भाव के बाद से डिजिटल मीडिया में अंग्रेजी के अलावा विश्व की उन सभी भाषाओं में विचारों का आदान-प्रदान संभव हो गया है जिनकी लिपि उपलब्ध है। इससे वैश्विक स्तर पर भाषायी क्रांति हो गई है। पहले सभी प्रकार के डिजिटल ज्ञान के लिए केवल अंग्रेजी भाषा पर आश्रित रहना पड़ता था। यूनिकोड के आने के बाद अब किसी भी भाषा में डिजिटल मीडिया के माध्यम से संचार किया जा सकता है। इससे विभिन्न भाषा-भाषी अपनी भाषा में समाचार और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत हो रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षिक सामग्री विकसित की जा रही हैं। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो उनके अनुसंधान और विकास में सहायक है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये विद्याएँ अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं थीं। भारतीय आचार्यों, मनीषियों का ज्ञान-विज्ञान विश्व में सर्वाधिक रहा है भारतीय नक्षत्र विज्ञान, आयुर्वेदिक चिकित्सा विश्व में कल भी सर्वश्रेष्ठ थीं आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं।

चुनौतियाँ और समाधान-

भाषाई विविधता और एकता : भारत की भाषाई विविधता भारत की समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन कभी-कभी यह एकता में विघटन का कारण बन जाती है। विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच भाषा के आधार पर आंतरिक कलह रह रहकर उभर आती है। अमृत काल में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से सभी भाषा भाषियों में परस्पर संवाद, सहयोग और समझ बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भाषाई सौहार्द और एकता को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों में परस्पर मतभेद समाप्त होंगे। जब सभी अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से एक-दूसरे की संस्कृति और विरासत को जानेंगे तो उसका लाभ सभी को होगा। वास्तव में भाषा एक-दूसरे को जोड़ने का काम करती है ये विचारों, ज्ञान और संस्कृति का एक सेतु बनाती है जिससे लोग एक-दूसरे के करीब आ सकें अमृत काल के दौरान यही सेतु सभी भारतीयों को न केवल एक-दूसरे के बल्कि अन्य विश्व के भी करीब ले जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तकनीकी चुनौतियाँ : डिजिटल युग में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए अमृत काल में इन भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर, ऐप्स की-बोर्ड और भाषाई उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इन भाषाओं के लिए तकनीकी समाधान प्रदान कर रहे हैं। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में वॉइस टाइपिंग की सुविधा अब उपलब्ध है।

अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमृत काल भारतीय भाषाओं के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का स्वर्णिम अवसर है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता से न केवल भाषाई समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज को भी मजबूती मिलेगी। यही समय है जब हम अपनी भाषाओं को गर्व और सम्मान के साथ अपनाएँ और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाते हुए विकसित भारत का निर्माण कर अपने विश्वगुरु के दर्जे को पुनः प्राप्त करें।

(साभार - राजभाषा भारती) ■

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में घोषित 'अमृत काल' न केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन का भी स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करता है। इस काल में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सहभागिता, उनका विकास, परस्पर संवाद और सांस्कृतिक समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है कोई भी राष्ट्र बिना भाषाओं के उत्थान एवं विकास के अपने आप को विकसित राष्ट्र नहीं कह सकता।

हिंदी पत्रकारिता के 200 साल

प्रो. संजय द्विवेदी
विभागाध्यक्ष, जनसंचार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि., भोपाल

संपादक के विस्थापन का कठिन समय!

हिंदी पत्रकारिता के 200 साल की यात्रा का उत्सव मनाते हुए हमें बहुत से सवाल परेशान कर रहे हैं जिनमें सबसे खास है 'संपादक का विस्थापन'। बड़े होते मीडिया संस्थान जो स्वयं में एक शक्ति में बदल चुके हैं, वहां संपादक की सत्ता और महत्ता दोनों कम हुई है। अखबारों से खबरें भी नदारद हैं और विचार की जगह भी सिकुड़ रही है। बहुत गहरे सौंदर्यबोध और तकनीकी दक्षता से भरी प्रस्तुति के बाद भी अखबार खुद को संवाद के लायक नहीं बना पा रहे हैं। यह ऐसा कठिन समय है जिसमें रंगीनियां तो हैं पर गहराई नहीं। हर तथ्य और कथ्य का बाजार पहले ढूंढा जा रहा है, लिखा बाद में जा रहा है।

नए समय में पत्रकारिता को सिर्फ कौशल या तकनीक के सहारे चलाने की कोशिशें हो रही हैं। जबकि पत्रकारिता सिर्फ कौशल नहीं बहुत गहरी संवेदना के साथ चलने वाली विधा है। जहां शब्द हैं, विचार हैं और उसका समाज पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पत्रकारिता के पारंपरिक मूल्य और सिद्धांत अप्रासंगिक हो गए हैं या नए जमाने में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। डिजीटल मीडिया की मोबाइल जनित व्यस्तता ने पढ़ने, गुनने और संवाद का सारा समय खा-पचा लिया है। जो मोबाइल पर आ रहा है,वही हमें उपलब्ध है। हम इसी से बन रहे हैं, इसी को सुन और गुन रहे हैं। ऐसे खतरनाक समय में जब अखबार पढ़े नहीं, पलटे जाने की भी प्रतीक्षा में हैं। दूसरी ओर व्हाट्सअप में अखबारों के पीडीएफ तैर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पीडीएफ पर ही छपते हैं। अखबारों को हाथ में लेकर पढ़ना और ई-पेपर की तरह पढ़ना दोनों के अलग अनुभव हैं। नई पीढ़ी मोबाइल सहज है। उसने मीडिया घरानों के एप मोबाइल पर ले रखे हैं। वे अपने काम की खबरें देखते हैं।

'न्यूज यू कैन यूज' का नारा अब सार्थक हुआ है। खबरें भी पाठकों को चुन रही हैं और पाठक भी खबरों को चुन रहे हैं। यह कहना कठिन है कि अखबारों की जिंदगी कितनी लंबी है। 2008 में 'प्रिंट इज डेट किताब' लिखकर जे. गोमेज इस अवधारणा को बता चुके हैं।

सवाल यह नहीं है कि अखबार बचेंगे या नहीं मुद्दा यह है कि पत्रकारिता बचेगी या नहीं। उसकी संवेदना, उसका कहन, उसकी जनपक्षधरता बचेगी या नहीं। संपादक की सत्ता पत्रकारिता की इन्हीं भावनाओं की संरक्षक थी। संपादक अखबार की संवेदना, भाषा, उसके वैचारिक नेतृत्व,समाजबोध का संरक्षण करता था। उसकी विदाई के साथ कई मूल्य भी विदा हो जाएंगें। गुमनाम संपादकों को अब लोग समाज में नहीं जानते हैं। खासकर हिंदी इलाकों में अब पहचान विहीन और 'ब्रांड' वादी अखबार निकाले जा रहे हैं। अब संपादक के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिखने न लिखने से भी फर्क नहीं पड़ता। न लिखे तो अच्छा ही है। पहचानविहीन चेहरों की तलाश है, जो अखबार के ब्रांड को चमका सकें। संपादक की यह विदाई अब उस तरह से याद भी नहीं की जाती। पाठकों ने 'नए अखबार' के साथ अनुकूलन कर लिया है। 'नया अखबार' पहले पन्ने पर भी किसी भी प्रोडक्ट का एड छाप सकता है, संपादकीय पन्ने को आधा कर विचार को हाशिए लगा सकता है। खबरों के नाम पर एजेंडा चला सकता है। 'सत्य' के बजाए यह 'नरेटिव' के साथ खड़ा है। यहां सत्य रचे और तथ्य गढ़े जा सकते हैं। उसे बीते हुए समय से मोह नहीं है वह नए जमाने का 'नया अखबार' है। वह विचार और समाचार नहीं कंटेट गढ़ रहा है। उसे बाजार में छा जाने की ललक है। उसके टारगेट पर खाये-अघाए पाठक हैं जो उपभोक्ता में तब्दील होने पर आमादा हैं। उसके कंटेंट में लाइफ स्टाइल की प्रमुखता है। वह जिंदगी को जीना और मौज सिखाने में जुटा है। इसलिए उसका जोर फीचर पर है, अखबार को मैग्जीन बनाने पर है। अखबार बहुत पहले 'रंगीन' हो चुका है, उसका सारा ध्यान अब अपने सौंदर्यबोध पर है। वह 'प्रजेंटेबल' बनना चाहता है। अपनी समूची प्रस्तुति में ज्यादा रोचक और ज्यादा जवान। उसे लगता है कि उसे सिर्फ युवा ही पढ़ते हैं और वह यह भी मानकर चलता है कि युवा को गंभीर चीजें रास नहीं आतीं।

यह 'नया अखबार' अब संपादक की निगरानी से मुक्त है। मूल्यों से मुक्त। संवेदनाओं से मुक्त। भाषा के बंधनों से मुक्त। यह भाषा सिखाने नहीं बिगाड़ने का माध्यम बन रहा है। मिश्रित भाषा बोलता हुआ। संपादक की विदा के बहुत से दर्द हैं जो दर्ज नहीं है। नए अखबार ने मान लिया है कि उसे नए पाठक चुनने हैं। बनाना है उन्हें नागरिक नहीं, उपभोक्ता। ऐसे कठिन समय में अब सक्रिय पाठकों का इंतजार है। जो इस बदलते अखबार की गिरावट को रोक सकें। जो उसे बता सकें कि उसे दृश्य माध्यमों से होड़ नहीं करनी है। उसे शब्दों के साथ होना है। विचार के साथ होना है।

हिंदी के संपादकाचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर ने कहा था, ''पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धनियों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे। आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्द्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पकता होगी, गंभीर गवेषणा की झलक होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी। यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी- इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। वेतनभोगी संपादक मालिक का काम करेंगे और बड़ी खूबी के साथ करेंगे। वे हम लोगों से अच्छे होंगे। पर आज भी हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह उन्हें न होगी। वस्तुतः पत्रों के जीवन में यही समय बहुमूल्य है।''

श्री पराड़कर की यह भविष्यवाणी आज सच होती हुई दिखती है। समानांतर प्रयासों से कुछ लोग विचार की अलख जगाए हुए हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अपने पाठकों के सक्रिय सहभाग से मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए आगे आएं। तभी उसकी सार्थकता है। ■

मैं घर आता हूँ

मैं घर आता हूँ
कभी थक कर, कभी हँस कर,
सुख का त्याग करके
तो कभी सुख की आस में।
शयन मिले मुझे,
ना मिले किसी और को,
या मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया।
मैंने ढूँढा तो बस मुझे
कभी एकांत को,
तो कभी दोस्तों के चुटकुले में।
मुझे हमेशा लगा,
मैं कहीं और हूँ
यहाँ नहीं, कहीं और।
किसके पीछे? किसके साथ?
मैं तो कहीं और हूँ।
मुझे अच्छा लगा,
अच्छा लगते-लगते इतना लगा
कि अच्छा लगना ही छूट-सा गया।
मैं छूटा या वो अच्छाई?
कदाचित् जीना ही छूट गया।
पर-जीना क्या होता है?
सुख की आस या
प्रश्न की प्यास
लगता था जानता हूँ,
पर मैं नहीं जानता हूँ।
कभी खुद को, कभी जीवन को।
जानते-जानते
मैं घर आता हूँ।

- अथर्व दयाल शर्मा

अंत्योदय से भारत निर्माण

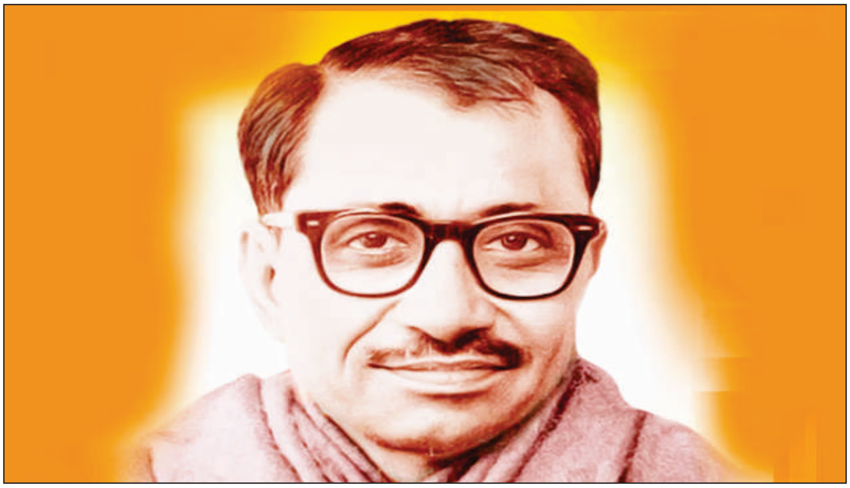

शीतल गहलोत
लेखिका

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। जिसकी आत्मा सदैव 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के आदर्श में बसी हुई है।आज के भारत में विकास की चर्चा जब भी होती है, तो प्रायः विदेशी मॉडल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवाद के पश्चिमी रूपों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन भारत की आत्मा और उसकी जीवन दृष्टि इससे कहीं आगे और गहरी है। यहां समाज का मूल आधार है, सबका उत्थान सब की भागीदारी। इसी भाव को 20वीं शताब्दी के प्रखर राष्ट्रवादी, राष्ट्र नायक, चिंतक, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के रूप में प्रस्तुत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत में लोकतंत्र के उन पुरोधाओं में से एक थे, जिन्होंने इसके उदार और भारतीय स्वरूप को गढ़ा है। उनके द्वारा बोए गए विचारों और सिद्धांतों के बीजों ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने का काम किया है।

उनकी विचारधारा सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए थी। भारत को उसके गौरव पद पर पुनर्स्थापित करने के लिए थी। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम वंचित गरीब व्यक्ति तक सुविधा और विकास नहीं पहुंचते हैं, तब तक देश की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।उन्होंने राजनीति में सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवेश नहीं किया, बल्कि हार कर भी मतदाताओं का धन्यवाद करने और विजयी प्रत्याशी को लोकहित में सहयोग की घोषणा की दृष्टि से महान भारत की रचना के लिए काम किया था। वह कहते थे कि हमें आधुनिक तो बनना है, लेकिन पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का मापदंड समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। इसलिए उन्होंने राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति तीनों के केंद्र में अंतिम व्यक्ति का उत्थान रखा। यही अंत्योदय दृष्टिकोण भारतीय चिंतन को पश्चिमी धारणाओं से अलग करता है।

अंत्योदय की अवधारणा है समाज का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे असहाय व्यक्ति भी आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सके। यह विचार केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें स्वरोजगार, स्वदेशी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, आत्म सम्मान, और सामाजिक न्याय सब कुछ शामिल हैं। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत व्यक्तिगत हितों को सामूहिक दृष्टिकोण के साथ मिश्रित किया। उपाध्याय ने समग्र मानववाद (integral humanism)का दर्शन प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिकवाद के साथ एकीकृत करने के संतुलित दृष्टिकोण को भारत के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके विचार भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा दर्शन थे। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता का एकीकरण चाहते थे।

आज हम भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस के रूप में मना कर उनके एकात्मक मानववाद और राष्ट्र उत्थान के अंत्योदय दृष्टिकोण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। राष्ट्रधर्म (मासिक), पांचजन्य (साप्ताहिक) और स्वदेशी (दैनिक) पत्रिकाएं उनके राष्ट्रवाद का ही दर्शन है। आजादी के बाद भारत में पश्चिमी मॉडल पर आधारित योजनाएं बनाई। भारी उद्योग, बड़े बांध और नगरों का विकास हुआ। लेकिन ग्रामीण भारत सदैव उपेक्षित रहा। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर सीमित रहे। किसान, मजदूर, गरीबी और कर्ज के बोझ से दबे रहे। दलित, आदिवासी और महिलाएं सामाजिक

न्याय से वंचित रहे। इस असंतुलन को साधने में पंडित उपाध्याय का अंत्योदय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जेपी नड्डा के अनुसार '2014 से पहले 18000 गांव बिना बिजली के थे। लेकिन 2014 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इन तीनों देशों की जनसंख्या को मिलाकर लोग भारत में केवल आयुष्मान योजना के अंतर्गत ₹500000 सालाना के हेल्थ कवर का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.13 करोड़ आवास निर्धन परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास और आर्थिक यात्राएं अंत्योदय से ही शुरू हुई हैं।आज भारत सरकार की अनेक योजनाएं अंत्योदय की भावना को आत्मसात कर रही है –

- ♦ प्रधानमंत्री जनधन योजना
- ♦ उज्ज्वला योजना
- ♦ आयुष्मान योजना
- ♦ प्रधानमंत्री आवास योजना
- ♦ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- ♦ ग्राम सड़क योजना

अंत्योदय अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाओं द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह सब योजनाएं प्रमाण है कि उपाध्याय का अंत्योदय आज भी नीति निर्माण का आधार है। पंडित दीनदयाल जी का आर्थिक दर्शन अंत्योदय के लिए बेहद प्रासंगिक है।

उन्होंने भारतीय मूल्यों पर आधारित एक संतुलित आर्थिक व्यवस्था की वकालत की, जो वर्तमान भारत का मार्गदर्शन कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लिए सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर करके पूरी शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया है। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। ऐच्छिक 550 लाख युवक युवतियों को स्थायी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस विचार को आधार बनाकर अनेक योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ गरीब और वंचित वर्ग को मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को भूख की समस्या से मुक्त किया है। यह पहल विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई थी।

> **"आर्थिक योजनाओं तथा प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। देश में ऐसे करोड़ों मानाव हैं, जो मानव के किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं कर पातें हैं।"**
>
> **- पं. दीनदयाल उपाध्याय**

स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाया है। अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे गंभीर बीमारियों का उपचार अब गरीब परिवारों के लिए किसी बोझ का कारण नहीं रहा। गरीबी के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने 'जीरो पॉवर्टी अभियान' की शुरुआत की है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास, किसान सम्मान निधि, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, रोजगार और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसका लक्ष्य प्रदेश को गरीबी से मुक्त बनाना है।आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)' योजना ने स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर खोले हैं। इससे स्वदेशी की भावना के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।स्पष्ट है कि योगी सरकार ने अन्त्योदय को केवल नारा न बनाकर व्यवहार में उतारा है। खाद्य, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की इन योजनाओं ने गरीब वर्ग को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है। यही वास्तविक अन्त्योदय है।नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित की गई है।

इन योजनाओं से लोगों की आजीविका में स्थाई सुधार होगा। ग्राम पंचायत, नामित अधिकारी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची बनाते हैं। हर भारतीय नागरिक को उनका सहयोग करना चाहिए और सही जानकारी जुटाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में योजना के हकदार लोगों को खोजना बहुत बड़ा काम है। वास्तव में अंत्योदय समाज की नैतिक प्रतिबद्धता है, कि विकास उस कमजोर वर्ग तक पहुंचे जहां राष्ट्र की प्रगति का उत्कृष्ट मापदंड अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो। अंत्योदय आधुनिक भारत के सामने आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों के समाधान हेतु एक सच्चे मार्गदर्शक के सिद्धांत के रूप में सहायतार्थ खड़ा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूरदर्शिता का परिणाम है और भारत सरकार का मार्गदर्शन है। केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय के समग्र मानववाद के दर्शन को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। ■

क्यों बढ़ रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में आपदायें?

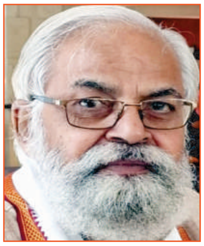

ज्ञानेन्द्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद्

बीते कुछ सालों से हिमालय का पर्वतीय अंचल आपदाओं के कहर से दो-चार हो रहा है। वह चाहे 2013 की केदारनाथ की आपदा हो, 2021 में ऋषिगंगा की हो, सिक्किम की 2023 की ल्होनक में ग्लेशियर झील के फटने की हो, जोशीमठ की घटना हो, बीते दिनों धराली में बादल फटने की घटना हो या फिर किश्तवाड की घटना हो, इन सबके पीछे जलवायु परिवर्तन तो एक अहम कारण है ही, मानसून कहें या मौसम में आये अप्रत्याशित बदलाव, अरब सागर में गर्म होती हवायें, मध्य एशिया में तेजी से बढ़ता तापमान और दक्षिण -पश्चिमी हवाओं का उत्तर की ओर झुकाव और उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में बारिश का तूफानी पैटर्न तो है ही, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण प्रकृति में इंसानी दखल भी है जिसका खामियाजा हम भीषण तबाही के रूप में साल दर साल ऐसी आपदाओं के नतीजे के रूप में भुगत रहे हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता।

असलियत यह है कि यह सब प्राकृतिक आपदायें हमारी नीतिगत विफलताओं का जीता-जागता सबूत हैं जबकि बरसों से समूची दुनिया के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समय-समय पर जारी रिपोर्टें, शोध और अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ों पर अवैज्ञानिक और अनियोजित निर्माण, पहाड़ों को काटकर या विस्फोट के जरिए नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं, रेल मार्ग का निर्माण, बेतहाशा खुदाई, नदी-नालों के कुदरती मार्गों में अवरोध पैदा करने से आपदाओं को हम खुद-ब-खुद निमंत्रण दे रहे हैं। किंतु विकास के नाम पर प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि संवेदनशील भूस्खलन वाले इलाकों में भी बहुमंजिला इमारतों, होटलों और सड़कों का निर्माण आज भी अनियंत्रित रूप से निर्बाध जारी है। यहां यह गौरतलब है कि जब धरती की सतह बार-बार खोदी जाती है, पहाड़ों का सीना बारम्बार चीरा जाता है, काटा जाता है, उस स्थिति में बारिश की हर बूंद उस नाजुक धरातल को चीरते हुए बहुत तेजी से बह निकलती है। नतीजतन मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ती है और आपदा का आकार कईसौ गुणा बढ जाता है। यही वह अहम कारण है कि ऐसी स्थिति में पहाड़ों पर भूस्खलन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

वैज्ञानिक बार-बार चेता रहे हैं कि जलवायु में आ रहे बदलाव और पहाड़ों पर विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण विनाश का कारण बन रहा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि ऊंचे इलाकों में एक डिग्री तापमान बढ़ने पर वर्षा की तीव्रता 15 फीसदी बढ़ जाती है। यह कि जब गर्म समुद्री हवा भारी नमी लेकर हिमालय से टकराती हैं तब पहाड़ उसे रोकते हैं। इससे क्यूम्यलोनिम्बस बादल बनते हैं जो 50,000 फीट ऊंचाई तक जा सकते हैं और जब ये फटते हैं तो अपने साथ पूरी की पूरी घाटी में भीषण तबाही लाते हैं। इस बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी आर डी ओ की मानें तो हिमालय के ग्लेशियर हर साल औसतन 15 मीटर पीछे खिसक रहे हैं या पीछे हट रहे है। कहीं- कहीं कुछ इलाकों में ग्लेशियर के पीछे हटने की दर 20 मीटर से भी ज्यादा है। इनमें गंगा बेसिन 15.5 मीटर प्रति वर्ष, इंडस बेसिन 12.7 मीटर प्रति वर्ष और ब्रह्मपुत्र बेसिन 20.2 मीटर प्रति वर्ष खिसक रहे हैं, शामिल हैं। दरअसल जब-जब और जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके नीचे की जमीन अस्थिर होती जाती है। पिघलती बर्फ, दरकती चट्टानें और अचानक बनने वाली झीलें सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इनके टूटने से भयंकर तबाही आती है, गांव के गांव बह जाते हैं और करोड़ों-करोड की हानि होती है सो अलग। एक रिपोर्ट की मानें तो साल 2018 तक कराकोरम और हिन्दू कुश जैसे इलाकों में

127 बडे ग्लेशियर संबंधित भूस्खलन रिकॉर्ड हुये हैं।

असलियत यह है कि हिमालयी क्षेत्र 13 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम सहित केन्द्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। मानसून के दौरान इनको अधिकाधिक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये अपनी जटिल बनावट,नाज़ुक हालातों और लगातार बदल रही जलवायु परिस्थितयों की वजह से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, बादल फटने और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आने वाली बाढ के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। ये आपदायें आबादी क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। बादल फटने और बाढ आने क दौरान किसी एक इलाके में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा या यूं कहें कि भीषण तबाही का सामना करना पड़ता है। चूंकि इस इलाके में अधिकांश नदियां संकरी घाटियों से होकर बहती हैं, बादल फटने या ग्लेशियर झील के फटने के चलते पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी मात्रा में मलवा भी आ जाता है। नतीजतन नदियों के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और निचले इलाकों में बाढ की स्थिति बन जाती है। एक आकलन के मुताबिक 2013 से लेकर 2022 के बीच पूरे देश में 156 आपदायें दर्ज हुयी जिनमें से 68 हिमालयी क्षेत्र में हुयीं। देखा जाए तो देश के भौगोलिक क्षेत्र में 18 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले इस क्षेत्र में आपदाओं की हिस्सेदारी करीब 44 फीसदी है। यही नहीं 1903 से लेकर अबतक इस क्षेत्र में दर्ज 240 आपदाओं में 132 बाढ़ संबंधी, 37 भूस्खलन की, 23 तूफान की, 17 भूकंप की व 20 से अधिक चरम तापमान की दर्ज हुयी हैं।

यह कटु सत्य है और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय इलाकों में जारी विकास परियोजनाओं से इस इलाके में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह इलाका तेजी से गर्म हो रहा है। इससे आपदाओं के बढ़ने की आशंका और बलवती हुयी है। 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 में उत्तराखंड में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बहने से पानी के तेज बहाव से धौलीगंगा में चट्टानें और मलवा आने से 200 से ज्यादा की मौत हुयी थी। गौरतलब है कि हिमालयी इलाके में बरसों से जारी खनन से नदी तल का क्षरण हो रहा है। इसके चलते नदियां सूख रही हैं,नतीजतन बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। खनन से नदी तल की बजरी, रेत और पत्थर निकल जाने से नदी का तल गहरा हो जाता है। खनन से भूमि कटाव और भूस्खलन की घटनायें बढ़ जाती हैं। यही नहीं खनन से निकलने वाले रसायन मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते हैं। खनन से वन्य जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं जिससे जैव विविधता को काफी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से हिमालयी ग्लेशियर पहले से ही पिघल रहे हैं। खनन से इसमें और तेजी आ रही है। खनन से जहां लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों की आजीविका, कृषि और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खनन से पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक दोनों तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। इन खतरों को कम करने के लिए खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और टिकाऊ विकास को बढावा दिये जाने की बेहद जरूरत है।

असलियत यह है कि यह सब प्राकृतिक आपदायें हमारी नीतिगत विफलताओं का जीता-जागता सबूत हैं जबकि बरसों से समूची दुनिया के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और समय-समय पर जारी रिपोर्टें, शोध और अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ों पर अवैज्ञानिक और अनियोजित निर्माण, पहाड़ों को काटकर या विस्फोट के जरिए नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं, रेल मार्ग का निर्माण, बेतहाशा खुदाई, नदी-नालों के कुदरती मार्गों में अवरोध पैदा करने से आपदाओं को हम खुद-ब-खुद निमंत्रण दे रहे हैं।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से यह अभी भी अधपकी है। यह अभी भी बदलाव के दौरान से गुजर रही है। यह जानते-समझते हुये भी हम वहां पर बेतहाशा कंक्रीट का निर्माण करते जा रहे हैं। बसावट कर रहे हैं। इसमें हमने नदियों के जलग्राही क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा। जब हम वहां जाकर बसेंगे तो भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनायें तो आयेगी हीं। इस सबके लिए हमें तैयार रहना होगा और इससे बचाव की दिशा मे प्रकृति अनुरूप साधन अपनाने होंगे। प्रकृति की संवेदनशीलता के प्रति हमें अति संवेदनशील होना होगा। यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करेगे तो निश्चित है कि हमें ऐसी आपदाओं से आये-दिन दो-चार होना पड़ेगा। सरकार के साथ हमारी भी जबावदेही है। हमें व सरकार को भूविज्ञानियों, पर्यावरणविदों की संस्तुति को मानना होगा जिन्हें हम बराबर नकारते आ रहे हैं और जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक पर्यावरणीय दृष्टि से अर्ली वार्निंग प्रणाली पर तत्काल काम करना होगा और क्षेत्र वार आपदा जोखिम की पहचान के साथ-साथ उसके न्यूनीकरण के लिए भी हर समय न केवल तैयार रहना होगा बल्कि उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम भी करना होगा। यह जानते हुए कि पर्वतीय इलाकों में मैदानी इलाको की तरह काम नही हो सकता। इसके लिए अलग दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि प्रकृति की राह में यदि हम आये तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना होग। ■

सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति : भारत की रैंकिंग में बढ़ोतरी

अनिरुद्ध गौड़
वरिष्ठ पत्रकार

17 सतत् विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में 14 से 23 जुलाई, 2025 के बीच आयोजित हुई उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) के विकास एजेंडा और 17 सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 की प्रगति को लेकर बैठक में जारी दसवीं रिपोर्ट में पाया गया कि सतत् विकास 2030 अपनाने से वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है लेकिन चिंता की बात है कि अभी भी बहुत से देश इन लक्ष्यों को पाने में बहुत दूर हैं। सिर्फ 5 साल बचे हैं और वैश्विक प्रगति पटरी पर नहीं है। विश्व के अधिकतर देश लक्ष्यों की प्रगति में काफी दूर हैं।

इस बार 2025 के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की थीम थी कि 2030 एजेंडा और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टिकाऊ, समावेशी, विज्ञान आधारित और साक्ष्य आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना है ताकि कोई पीछे न छूट जाए।

विश्व रैंकिंग में 100 देशों की श्रेणी में भारत : भारत की उपलब्धि की बात करें तो कुल 193 देशों में इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को पाने में भारत ने निर्धारित अधिकतम 100 अंकों में 66.95 अंक प्राप्त कर 99वां स्थान पाया है। पिछले साल 2024 में एसडीसी लक्ष्यों की प्रगति में भारत 109वें और 2023 में 112वें स्थान पर था। सतत् विकास लक्ष्यों को पाने में इस साल भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विश्व रैंकिंग में 100 देशों की श्रेणी में स्थान बनाया है। हालांकि भारत को 2030 तक सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। क्योंकि कई क्षेत्रों में भारत पिछड़ा हुआ है। भारत के पड़ौसी देश बंगलादेश (114वें) और पाकिस्तान (140वें) स्थान को छोड़ दिया जाए तो चीन 49वें, भूटान 74वें, नेपाल 85वें स्थान पर एसडीजी लक्ष्यों को पाने में भारत से आगे हैं। यही नहीं लक्ष्यों की प्रगति में समुद्री पड़ौसी देश मालदीप 53वें और श्रीलंका 93वें स्थान के साथ भारत से आगे चल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनैतिक फोरम (एचएलपीएफ) हर साल न्यूयार्क में आयोजित होता है, जिसमें सदस्य देशों के सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर समीक्षा की जाती है। गत 14 से 23 जुलाई के बीच संपन्न 10 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन जारी दसवीं रिपोर्ट दर्शाती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में विश्व स्तर पर प्रगति से लाखों लोगों के जीवन में सुधार तो आया है लेकिन 2030 तक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रगति धीमी चल रही है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अभी केवल 35 प्रतिशत लक्ष्य ही ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और 31 प्रतिशत लक्ष्यों में मामूली प्रगति है। जबकि 17 प्रतिशत में ठहराव आया हुआ है और 18 प्रतिशत लक्ष्य की अपेक्षा बहुत पीछे चल रहे हैं। एसडीसी संकल्प के 10 साल बाद एजेंडा 2030 को कई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों में विकास के लिए चार हजार अरब डालर की कमी है। भूराजनैतिक तनाव के कारण भी बहुपक्षवाद पर आधारित व्यवस्थाएं ढीली पड़ रही हैं।

स्थिति यह है कि 2025 की सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट में किसी भी देश ने अपने सतत् विकास लक्ष्यों में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में अभी तक सफलता नहीं पायी है। तमाम विकसित देश भी 10 साल के बाद भी एसडीसी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं। हालांकि 87.02 प्रतिशत अंक प्राप्त कर फिनलैंड सतत् विकास लक्ष्य पाने में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, पोलैंड और चेकिया प्रथम दस स्थान में हैं।

सतत विकास लक्ष्यों के संकल्प के इतिहास में जाएं तो अब से दस वर्ष पहले 25 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में संपन्न संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने विश्वस्तर पर आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के विभिन्न आयामों को संतुलित करने

के प्रयास को लेकर 17 वैश्विक लक्ष्य और इनसे जुड़े 169 विशिष्ट लक्ष्यों को अपनाया था। इन 17 लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन, जमीन पर जीवन, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं और साझेदारियां शामिल हैं। साथ ही इन लक्ष्यों को 1 जनवरी 2016 से 2030 तक 15 वर्षो में पूरा करने के लिए सभी देशों ने प्रतिबद्धता भी जतायी थी। तब से इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक देश की प्रगति के तौर पर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट जारी की जाती है। ताकि यह मालूम हो कि किस देश ने अभी तक कितने लक्ष्यों को पूरा किया है। लेकिन चिंता की बात है कि अभी सिर्फ पाँच वर्ष रह गए हैं और काफी देश लक्ष्यों को पाने में किए गए संकल्प से काफी पीछे हैं।

चुनौतियों के बाबजूद लक्ष्यों में प्रगति : विश्व में काफी उथल-पुथल है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल और गाजा के अलावा ईरान, सीरिया आदि में युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जैसे एचआईवी संक्रमण में लगभग 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। मलेरिया की रोकथाम से 2. 2 बिलियन मामलों को रोका गया, जिससे 12.7 मिलियन लोगों की जान बच पाई। अब 110 मिलियन से अधिक बच्चे और युवा स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं। जबकि विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या तक सामाजिक सुरक्षा पहुंच गई है। यही नहीं विश्व की 92 प्रतिशत आबादी तक 2023 से अब बिजली पहुंच गई है। 2015 में 40 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे जो 2024 में 68 प्रतिशत तक हो गया है

सतत् विकास लक्ष्यों पर जारी वर्तमान रिर्पोट कई चुनौतियों की ओर भी ध्यान इंगित करती है। इनमें 800 मिलियन से अधिक लोग अभी भी गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। विश्व के करोड़ों लोगों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली हैं। जलवायु परिवर्तन का भी काफी प्रभाव है। 2024 विश्व का सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिससे तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो रहा है। वैश्विक शरणार्थी आबादी भी बढ़ रही है। विश्व में 1.12 अरब लोग बुनियादी सेवाओं के बिना झुग्गी झोपड़ियों या अस्थाई बस्तियों में रहते हैं।

पिछले साल 2024 में एसडीसी लक्ष्यों की प्रगति में भारत 109वें और 2023 में 112वें स्थान पर था। सतत् विकास लक्ष्यों को पाने में इस साल भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विश्व रैंकिंग में 100 देशों की श्रेणी में स्थान बनाया है। हालांकि भारत को 2030 तक सभी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे।

इन क्षेत्रों में हुई प्रगति : लक्ष्यों में प्रगति की बात की जाए तो 2012 और 2024 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापान 26.4 प्रतिशत से घटकर 23.2 प्रतिशत रह गया है। जीवन प्रत्याशा में 1.8 वर्ष की कमी तो वैश्विक मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्मों पर 228 से घटकर 197 हुई है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 16 प्रतिशत की कमी आई है। भेदभाव पूर्ण कानून को हटाने और लैंगिक समानता ढांचे को स्थापित करने में सकारात्मक कानूनी सुधार लागू हुए हैं। राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी से ऊर्जा स्रोत बढ़े है। वैश्विक जनसंख्या के 51 प्रतिशत तक मोबाइल ब्रॉडबैंड की पहुंच हुई है।

कई देशों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 45 देशों ने सार्वभौमिक बिजली तक पहुंच बनाई और 54 देशों ने 2024 के अंत तक कम से कम एक रोग का उन्मूलन किया। लेकिन रिपोर्ट में बहुत सी चुनौतियां से निपटने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति लाने के लिए तत्काल बहुपक्षीय कार्रवाई और वित्तीय सुधार लाने का आह्वान किया गया है। क्योंकि अधिकतर लक्ष्य 40 से 42 प्रतिशत तक हुए हैं।

दुनियाभर में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय बाधाएं एसडीजी लक्ष्यों तक पहुंचने में मुख्य तौर पर बाधक हो रहीं हैं। फिर भी एसडीजी लक्ष्य विश्व में गरीबी, भुखमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शांति और न्याय के क्षेत्र में सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। विश्व स्तर पर बहुपक्षीय सुधार, विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के प्रयास और सरकारों के आपसी संघर्षो को दूर करना होगा। इससे जो वित्त संघर्षो में खर्च हो रहा है वह पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत् विकास की योजनाओं में खर्च होने से कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अभी भी आशा है कि सतत् विकास लक्ष्य हमारी पहुंच में है लेकिन यह जब ही प्राप्त हो सकते हैं, जब हम तत्परता, एकता और अटूट संकल्प के साथ कार्य करेंगे। राजनैतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों को सही दिशा दी जाए तो सतत् विकास लक्ष्यों को अब भी हासिल किया जा सकता है। विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। टिकाऊ शांति के लिए टिकाऊ विकास जरूरी है।

भारत हर वर्ष अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार ला रहा है। गरीबी उन्मूलन में पिछले 10 वर्षों में 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुनी हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छ उर्जा सहित कई क्षेत्र में काफी प्रगति की है। लेकिन अभी भारत को अपने एसडीजी लक्ष्यों को पाने में तेजी लानी होगी। भारत की आबादी का असर ग्लोबल स्तर पर हो रहा है। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। इसके कारण महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भी हो रही है। डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी में भी भारत की काफी तरक्की है। सतत् विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में 'समूची सरकार और पूरे समाज की भागेदारी' भारत की सफलता की कुंजी रही है। ■

लव जिहाद
हिन्दू क्यों हार रहा नेरेटिव की लड़ाई

अजय सेतिया
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

देश में चल रहे मुसलमानों के "लव जिहाद" को कर्नाटक के प्रमोद मुथालिक ने बीस साल पहले पहचान लिया था। यह 2005 की बात है जब कर्नाटक के हावेरी जिले के सावनूर में एक 65 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति ने एक 19 वर्षीय गरीब हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया था। जब वह तीन महीने तक लापता रही, मुथालिक ने मामले की जांच की तो उन्हें पता चला था कि मुसलमान 'जिहाद' शब्द का इस्तेमाल 'धर्मयुद्ध' के लिए करते हैं। ऐसे कई मामले थे और यह महसूस करते हुए कि यह एक 'बड़ी साजिश' थी। मुथालिक ने इसे वर्णित करने के लिए शुरू में कन्नड़ में षडयंत्र और चालाक रणनीति शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में प्रमोद मुथालिक को एहसास हुआ कि यह जिहाद का एक रूप है, तब उन्होंने इसे "लव जिहाद" का नाम दिया।

पिछले बीस सालों में लव जिहाद के सैंकड़ों किस्से सामने आ चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा और स्वरा भास्कर ताजा उदाहरण हैं। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में तथाकथित शादी की है, इसका मतलब है कि दोनों जोड़ों ने निकाह नहीं किया है। लेकिन इस्लाम में यह मान्य ही नहीं है। दर्जनों केस सामने आ चुके हैं, जिनमें बाद में मुस्लिम लडके और उसके घर वालों ने हिन्दू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। देखते हैं सोनाक्षी और स्वरा कितने दिन तक बची रहती हैं। मंसूर अली खान पटौदी से निकाह करने के लिए शर्मिला टैगोर को आयशा सुल्ताना बनना पड़ा था। उसका बेटा सैफ अली खान बना। चलिए सोनाक्षी और स्वरा भास्कर धर्म परिवर्तन न भी करें, तो भी उससे पैदा होने वाले बच्चे मुस्लिम बनेंगे, जैसे नसीरुद्दीन शाह से शादी करने वाली रत्ना पाठक के बच्चे इमाद शाह और विवान शाह बनें, सैफ अली खान से शादी करने वाली करीना कपूर के बच्चे तैमूर और जेह अली खान बने। सोनाक्षी सिन्हा तो फिलहाल शांति से वैवाहिक जिन्दगी जी रही है, लेकिन स्वरा भाष्कर पूरी तरह मुस्लिम रंग में रंग गई हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नाम पर वोट करने की अपील की थी। उनकी वह अपील इस बात का प्रमाण है कि लव जिहाद देश की एकता, देश के संविधान, लोकतंत्र और हिन्दू

सांस्कृतिक विरासत के लिए कितना बड़ा खतरा है।

लेकिन अदालतें, सरकारें और वामपंथी विचारधारा के बुद्धिजीवी लव जिहाद को नकारते रहे हैं। 2020 में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी. कृष्ण रेड्डी ने भी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि लव जिहाद का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। स्वाभाविक है, जैसा कि यमुनानगर की अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश रंजना अग्रवाल ने कहा कि किसी कानून में लव जिहाद के लिए कोई आपराधिक धारा नहीं है, तो लव जिहाद के केस कैसे दर्ज होंगे। यमुनानगर की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल ने उस झूठे नेरेटिव पर से पर्दा हटा दिया है कि 'लव जिहाद' नाम की कोई चीज नहीं है। यह किस्सा 14 साल की एक बच्ची का है, जिसका एक मुस्लिम लड़का रोज पीछा करता था और 35 साल का शाहबाज उस हिन्दू बच्ची पर उस मुस्लिम लड़के से संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। अदालत ने शाहबाज को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि 'लव जिहाद' भारतीय न्याय संहिता या पोक्सो एक्ट के तहत कोई कानूनी शब्द नहीं, लेकिन अदालत ने इसे मुस्लिम पुरुषों का गैर-मुस्लिम युवतियों को प्यार का नाटक करके इस्लाम में बदलने का एक अभियान बताया है। इसका मतलब है कि कुछ मुस्लिम मर्द प्यार का दिखावा करके हिन्दू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं।

शुकर है यमुनानगर के केस में लडकी नाबालिग थी, इसलिए पोक्सो एक्ट में उसे सजा हो गई। वरना केरल का 2016 का अखिला अशोकन उर्फ हादिया केस याद कीजिए, सुप्रीमकोर्ट ने उसके पिता के एन अशोकन की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका इसलिए खारिज कर दी थी, क्योंकि अखिला 24 साल की थी। वह एक मुस्लिम युवक शफीन जहां के प्रेम जाल में फंस गई थी, उस मामले में शफीन जहां ने चालाकी यह भी की थी कि अखिला अशोकन से निकाह करने से छह महीने पहले ही उसे मुस्लिम मत में परिवर्तित करवा लिया था। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने बालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करना और मनमाफिक लड़के से शादी करना उसका संवैधानिक हक बता कर हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया था।

मुसलमान 'जिहाद' शब्द का इस्तेमाल 'धर्मयुद्ध' के लिए करते हैं। ऐसे कई मामले थे और यह महसूस करते हुए कि यह एक 'बड़ी साजिश' थी। मुथालिक ने इसे वर्णित करने के लिए शुरू में कन्नड़ में षडयंत्र और चालाक रणनीति शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में प्रमोद मुथालिक को एहसास हुआ कि यह जिहाद का एक रूप है, तब उन्होंने इसे 'लव जिहाद' का नाम दिया।

अफसोस यह है कि सुप्रीमकोर्ट ने तो चलो संविधान की बात की, लेकिन भारत के मीडिया पर हिन्दू संस्कृति विरोधी वामपंथी पत्रकारों का कब्जा रहा है, जो लव जिहाद की हर खबर को महिलाओं के स्वतन्त्रता का अधिकार बताकर हिन्दुओं को रुढ़िवादी करार देता रहा है। उन्होंने यह नेरेटिव खड़ा कर दिया है कि यह कट्टरपंथी हिन्दुओं का गढ़ा हुआ शब्द है, वास्तव में लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। यह हिन्दू बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी कि लव जिहाद के मामले में वे प्रोपेगेंडा की जंग हार गए हैं, या हार रहे हैं। आप गूगल में जा कर लव जिहाद शब्द सर्च कीजिए, आपको लव जिहाद को हिन्दुओं का झूठा प्रोपेगेंडा बताने वाले दर्जनों लेख और रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, लेकिन लव जिहाद की वास्तविकता को उजागर करने वाला कोई एक लेख या रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा। हिन्दू यह नेरेटिव नहीं बना पाए कि जब मुस्लिम युवक अपना नाम हिन्दू बता कर और हाथों में कलेवा बाँध कर किसी हिन्दू लडकी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, तो वह लव जिहाद कैसे नहीं है। जब मुसलमान गैर मुस्लिम से निकाह कर ही नहीं सकता, तो यह लव जिहाद कैसे नहीं है। किसी गैर मुस्लिम महिला से निकाह करने से पहले उस महिला का मुस्लिम मत में परिवर्तन होना, निकाह की पहली शर्त है। हिन्दू युवतियों को उसका मुस्लिम प्रेमी यह कभी नहीं बताता कि इस्लाम में विवाह, शादी जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसी हिन्दुओं में सात फेरे लेते समय जीवन भर सुख दुःख में एक दूसरे का साथ निभाने का वायदा लिया जाता है, ऐसा इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम में निकाह एक कांट्रेक्ट है, जिसे मुस्लिम पुरुष निकाह के समय तय मेहर की राशि अदा करके कभी भी तोड़ सकता है। ■

विभिन्न समुदायों को उत्सवों के लिए एक साथ लाता सितम्बर

नीलम भागी
लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर एवं ट्रेवलर

इस माह के त्योहार दुनियाभर में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभवों का अनूठा मेल दिखाते हैं। कटाई के महीने की शुरुआत भी हो जाती है। गणपति उत्सव, दुर्गापूजा और ओणम तो चल ही रहा है। संगीत उत्सवों का आनन्द और बढ़ा भी देता है।

चक्रधर समारोह (2 से 12 सि.) संगीतमय चक्रधर समारोह भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता कलाप्रेमियों के लिए एक अमूल्य अनुभव है। छत्तीस के रायगढ़ का यह वार्षिक उत्सव महाराजा चक्रधर के सम्मान में भारतीय संगीत और नृत्य का जश्न मनाता है।

दक्षिण भारत में ओणम केरल का प्राचीन पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उत्सव हैं, जिसे दुनियाभर में मलयाली समाज मनाता है। 5 सितम्बर को इसका समापन होगा। केरल में चार दिन की छुट्टी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रत्येक वर्ष राजा महाबलि पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने आते हैं और नई फसल आने की खुशी भी होती है।

गणेशोत्सव आनन्द चतुर्थी (6 सितम्बर) दस दिन तक दक्षिण के कला शिरोमणि गणपति के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु गणपतिमय रहता है और पूरे देश में पूजा अर्चना के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। बप्पा के आवाहन से लेकर विसर्जन तक श्रद्धालु, आरती, पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, लगभग

सभी उपस्थित रहते हैं। घरों में भी गणपति 1,3,5,7,9 दिन बिठाते हैं। इसमें गौरी पूजन, दो दिन महालक्ष्मी पूजन, छप्पन भोग हैं। अष्टमी को ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौंरा अपने गणपति से मिलने आती हैं। उपवास रखकर, कुल्हड़ गुड़ियों के रुप में गौरी को पूजते हैं और सबको भोजन कराते हैं। अगले दिन शाम को आरती के बाद कीर्तन होता है। मंगलकारी बप्पा साल में एक बार तो आते हैं इसलिए उनके सत्कार में कोई कमी न रह जाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोदक, लड्डू के साथ तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं।

आनंद चतुर्दशी (6 सितम्बर) के दिन गणपति विसर्जन होता है। ढोल के साथ नाचते हुए गणपति से विनती करते हुए कहते हैं कि अगले बरस तूं जल्दी आ और विसर्जन जूलूस में जाते हैं।

गणपति की कथाएं बड़ी रोचक हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत की कथा लिखना चाह रहे थे पर उनके विचार प्रवाह की रफ्तार से, कलम साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने गणपति से लिखने को कहा। उन्होंने लिखना स्वीकार किया पर पहले तय कर लिया कि वे लगातार लिखेंगे, जैसे ही उनका सुनाना बंद होगा, वह आगे नहीं लिखेंगे। महर्षि ने भी गणपति से प्रार्थना कर, उन्हें कहा," आप भी एडिटिंग साथ-साथ करेंगे।" गणपति ने स्वीकार कर लिया। जहां गणपति करेक्शन के लिए सोच विचार करने लगते, तब तक महर्षि अगले प्रसंग की तैयारी कर लेते। वे लगातार कथा सुना रहे थे। दसवें दिन जब महर्षि ने आखें खोलीं तो पाया कि गणपति के शरीर का ताप बढ़ गया है। उन्होंने तुरंत पास के जलकुंड से जल लाकर उनके शरीर पर प्रवाहित किया। उस दिन भाद्रपद की चतुर्दशी थी। इसी कारण प्रतिमा का विर्सजन चतुर्दशी को किया जाता है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगलपूर्ति के नाम से पूजता है।

हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष (8 सितम्बर से 21 सितम्बर) का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितरों के निमित्त किए गए तर्पण से पितर, तृप्त होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जिससे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। महालय अमावस को पितृ विसर्जन करते हैं।

सृजन, निर्माण, वास्तुकला, औजार, शिल्पकला, मूर्तिकला एवं वाहनों के देवता विश्वकर्मा की जयंती (17 सितम्बर) को मनाई जायेगी। कारीगरों का यह उत्सव का दिन है। सब एक जगह इक्कट्ठा होकर पूजा करते हैं और फिर मूर्ति का विर्सजन करते हैं।

आभानेरी महोत्सव (17 से 19 सितम्बर) में कालबेलिया नृत्य, लंगा नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य, रास लीला, कठपुतली शो का आनन्द उठाते हुए हम राजस्थान की जातीय कलाकृतियां और हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। ऊँट गाड़ी की सवारी करते हुए फूलों और रंगोली की सजावट देखने लायक होती है। जयपुर से 80 किमी. दूर आभानेरी गाँव में चांद बावड़ी और हर्षत माता मंदिर के बीच में मनाया जाता है।

नीलमपेरूर पदायनी (21 और 22 सितम्बर) अलपुझा जिले में खूबसूरत गांव नीलमपेरूर में पल्ली भगवती मंदिर को उत्सव मनाने के लिए खूब सजाया जाता है। ओणम के महीने में होने से यह केरल में बहुत लोकप्रिय है। जिसमें पुतले लेकर एक जलूस निकाला जाता है।

अग्रसेन जयंती (22 सि.) को महान हिंदू राजा महाराजा अग्रसेन का जन्मदिन उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है।

शरदोत्सव दुर्गोत्सव (22 सि. से 2 अक्तूबर) एक वार्षिक हिन्दू पर्व है। जिसमें प्रांतों में अलग अलग पद्धति से देवी पूजन है। गुजरात का नवरात्र में किया जाने वाला गरबा नृत्य तो पूरे देश का हो गया है। जो नहीं करते वे देखने जाते हैं।

बतुकम्मा महोत्सव (22 सि. से 30सि):- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की महिलाओं द्वारा, बड़े उत्साह से पूरे नौ दिन मनाया जाने वाला बतुकम्मा महोत्सव हैं। ये शेष भारत के शरद नवरात्रि से मेल खाता है। प्रत्येक दिन बतुकम्मा उत्सव को अलग नाम से पुकारा जाता है। जंगलों से ढेर सारे फूल लाते हैं। फूलों की सात पर्तों से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाकर बतुकम्मा अर्थात् देवी माँ पार्वती को महागौरी के रूप में पूजा जाता है।

उत्तर भारत में नौ दिन तक देवी मंदिर सारा दिन खुले रहते हैं। भगवती जागरण, माता की चौंकी, भण्डारों का आयोजन किया जाता है। घरों में महिलाएं कीर्तन आयोजित करती हैं। जहां वे माबेाइल के जमाने में भी अपनी पुरानी भजनों की डायरियाँ लेकर जाती हैं।

महाअष्टमी और महानवमी को नौ बाल कन्याओं की पूजा की जाती है जो देवी नवदुर्गा के नौ रूपों का प्रतिनिधित्व करतीं हैं।

करणी माता महोत्सव दशनोक, बीकानेर राजस्थान में नवरात्र को मनाया जाता है। यहां नवरात्र में मेला लगता है।

तिरूमाला में ब्रह्मोत्सव (30 सि. से 8 अक्तू.) मनाया जा रहा है। किंवदंती है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले तिरूमाला में ब्रह्मोत्सव मनाया था। तिरूमाला में तो हर दिन एक त्यौहार है और धन के भगवान श्री

वेंकटेश्वर साल में 450 उत्सवों का आनन्द लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मोत्सव है। जिसका शाब्दिक अर्थ है 'ब्रह्मा का उत्सव' जिसमें हजारो श्रद्धालु इस राजसी उत्सव को देखने जाते हैं।

दशहरे की छुट्टियों में जगह-जगह रात को रामलीला मंचन, मंच पर होता है। जिसे बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं। लौटते हुए रामलीला के मेले से गत्ते, बांस, चमकीले कागजों से बने चमचमाते धनुष बाण, तलवार और गदा आदि शस्त्र खरीद कर लाते हैं और वे दिन में पार्कों में रामलीला का मंचन करते हैं। जिसमें सभी बच्चे कलाकार होते हैं। उन्हें दर्शकों की जरुरत ही नहीं होती। इन दिनों सारा शहर ही राममय हो जाता।

दुर्गा पूजा 28 सि. से 2 अक्तूबर) यह भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला सामाजिक -सांस्कृतिक धार्मिक वार्षिक हिन्दू पर्व है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, ओडिशा और त्रिपुरा में सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। नेपाल और बंगलादेश में भी बड़े त्यौहार के रुप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिमी भारत के अतिरिक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है। हिन्दू सुधारकों ने ब्रिटिश राज में इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रतीक भी बनाया। दिसम्बर 2021 में कोलकता की दुर्गापूजा को यूनेस्को की अगोचर सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।

बहू मेला जम्मू और कश्मीरः जम्मू में आयोजित होने वाले सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। यह जम्मू के बहू किले में नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। इस दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग रंगीन पोशाकें पहनते हैं और मेले में खरीदारी करते हैं और खाने के स्टॉल में वहां के पारम्परिक खानों का स्वाद लेते हैं।

तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक में दशहरे से पहले नौ दिनों को तीन देवियों की समान पूजा के लिए तीन तीन दिनों में बांट दिया है। पहले तीन दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। अगले तीन दिन शिक्षा और कला की देवी सरस्वती को समर्पित हैं। और बाकि तीन दिन माँ शक्ति दुर्गा को समर्पित हैं

जीरो संगीत महोत्सव (25 से 28 सि.) अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में आयोजित होने वाला यह चार दिवसीय संगीत महोत्सव है। जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दिखाता है। यह महोत्सव स्वतंत्र कलाकारों के लिए प्राकृतिक सुंदरता के बीच संगीत कला प्रेमियों को मंच देता है।

नीरसता को समाप्त करते हमारे पर्व आनन्द के साथ पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ■

'फास्ट' से पहचानें स्ट्रोक के लक्षण

डॉ. प्रशांत अग्रवाल
कंसलटेंट न्यूरो सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा

आम बोलचाल में स्ट्रोक को लकवा कहा जाता है। यह तब होता है जब दिमाग तक खून का बहाव अचानक रुक जाए या बहुत कम हो जाए। खून का यह प्रवाह रुकने से ब्रेन को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता और कुछ ही मिनटों में इसकी सेल्स मरने लगती हैं। इसी वजह से स्ट्रोक को मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। अगर समय पर पहचान और इलाज न हो, तो इससे स्थायी अपंगता या मौत तक का खतरा हो सकता है। दुर्भाग्य से कई लोग शुरुआती लक्षणों को समझ ही नहीं पाते और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

स्ट्रोक की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इसके लक्षण अचानक सामने आते हैं और अक्सर मामूली लगते हैं। चेहरे पर अचानक टेढ़ापन आ जाना, एक तरफ के हाथ या पैर में कमजोरी या उनका सुन्न होना महसूस हो, बोलने में दिक्कत या शब्द बिगड़ जाना, अचानक धुंधला दिखाई देना या सिर घूमना ऐसे संकेत हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह तेज सिरदर्द हो और इसके साथ उल्टी या चक्कर आ रहे हों, तो यह भी स्ट्रोक का इशारा हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि स्ट्रोक की पहचान में हर मिनट कीमती है। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा, ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।

स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे पहले इसके कारणों को समझना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल इसके मुख्य कारण हैं। अगर धमनियों में फैट जमा हो जाए तो खून का बहाव रुक सकता है। धूम्रपान और शराब जैसी आदतें इस खतरे को और बढ़ाती हैं। मोटापा और इन ऐक्टिव लाइफ स्टाइल भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ाने की वजह बनते हैं। वहीं जिन लोगों के परिवार में स्ट्रोक या हार्ट डिज़ीज की हिस्ट्री है, उनमें यह जोखिम और ज्यादा रहता है।

बचाव का सबसे आसान उपाय है नियमित जांच और लाइफस्टाइल में सुधार। ब्लड प्रेशर और शुगर का स्तर संतुलित रखना बेहद जरूरी है। खाने में तेल, मसाले वाली चीजों की जगह हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करना चाहिए। दिन में पर्याप्त पानी पीना और कम नमक लेना भी फायदेमंद है। रोज़ाना हल्की कसरत, तेजी से चलना, योग या प्राणायाम करने से खून का संचार बेहतर होता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन सही तरीके से मिलती है।

सिगरेट और शराब से दूरी बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि यह न केवल धमनियों को कमजोर करती हैं बल्कि ब्लड प्रेशर भी असामान्य कर देती हैं। नींद का पूरा होना भी स्ट्रोक से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। लगातार जागना और तनाव लेना दिमाग पर दबाव डालता है। संगीत सुनना, किताब पढ़ना या किसी शौक को समय देना मानसिक संतुलन बनाए रखता है।

अगर स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। समय गंवाने से मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं। कई बार लोग घरेलू इलाज या आराम का इंतजार करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्ट्रोक की पहचान के लिए दुनिया भर में एक आसान तरीका अपनाया जाता है, जिसे "फास्ट" कहा जाता है। इसमें चेहरे को देखें कि कहीं वह टेढ़ा तो नहीं हो रहा, हाथ उठाने को कहें कि कहीं कमजोरी तो नहीं है, बात करने को कहें कि बोली साफ है या नहीं और समय बर्बाद किए बिना तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। यह 'फास्ट' तरीका कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हुआ है।

स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है लेकिन इसका बचाव संभव है। अगर समय रहते जांच कराई जाए, खानपान और दिनचर्या में संतुलन लाया जाए और धूम्रपान जैसी आदतों से दूरी बनाई जाए तो स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक टाला जा सकता है। जागरूकता और सतर्कता ही इस बीमारी से बचने का सबसे मजबूत हथियार है। दिमाग हमारी सबसे कीमती पूंजी है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी है। ■

पर्यावरण जागरूकता के लिए समर्पित पीपल मैन

आज सारी दुनिया पर्यावरण के गंभीर संकट से गुजर रही है। अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से जीव-जंतुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। मनुष्य यदि समय रहते नहीं चेता तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा न हो इसके लिए प्रत्येक मानव को अपना-अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का, अपने आचरण का महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा। देश समाज में अनेक लोग और संस्थाएं पर्यावरण के लिए समर्पित होकर काम कर रही हैं ऐसी ही एक संस्था है रघुराज पीपल मैन फाउंडेशन। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले युवा डॉ. रघुराज प्रताप सिंह ने की है। यह फाउंडेशन पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण को लेकर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थानों से जुड़कर पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है।

हरियाली का विस्तार हो इसके लिए यह संस्था लाखों पौधारोपण कर चुकी है। संस्था ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पीपल, बरगद, पाकर, नीम, तुलसी जैसे पौधों का बड़े स्तर पर रोपण कर रही है। हरियाली और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी यह फाउंडेशन समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है। हमारे देश में अन्न की पूजा की जाती है, किसान को भी अन्नदाता होने का पारंपरिक सम्मान प्राप्त है। भारत की संस्कृति में नदी, पर्वत, पेड़-पौधे, जीव-जंतु सभी के प्रति सम्मान ही हमारी पहचान और परम्परा है। आजकल देखा जा रहा है कि अनेक लोग अपनी इस परम्परा को भूलते जा रहे हैं, खाने की थाली में जूठन छोड़ देते हैं, अन्न की बर्बादी होती है, यह भी पर्यावरण से जुडा एक गंभीर विषय है। संस्था विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और समाज के लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक कर रही है कि थाली में भोजन उतना ही लिया जाए जितना आप खा सकते हैं, पैसे से जरूर

डॉ. रघुराज प्रताप सिंह (पीपल मैन)

आप अधिक खरीद सकते हैं, पैसे आपके हैं लेकिन संसाधन सभी के हैं। यदि समाज का प्रत्येक सदस्य थाली में जूठन न छोड़ने का संकल्प ले तो न केवल हम अपनी महान संस्कृति का संरक्षण ही करेंगे अपितु ऐसे हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध हो सकेगा जिन्हें इसकी जरुरत है। संस्था शादी-विवाह और जन्मदिन और अन्य उत्सव आदि के अवसर पर पौधों का वितरण उपहार के रूप में कराना प्रारम्भ किया है। संस्था प्लास्टिक के उपयोग के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रही है क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग भी पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरण के लिए संस्था द्वारा किया जा रहा यह एक अच्छा प्रयास है। बच्चे तो इसमें बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं।

संस्था के प्रमुख डॉ. रघुराज प्रताप सिंह गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'धोलेरा ग्रीन सिटी' को धरातल पर साकार करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक केंद्र बने, बल्कि पौधारोपण और स्वच्छ ऊर्जा में भी अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरे। सितम्बर माह में संस्था एक देशव्यापी रैली के माध्यम से आयोजित एक करोड़ पौधारोपण अभियान में सम्मिलित हो रही है। 9 सितम्बर को इंडिया गेट से शुरू होने वाले इस अभियान में 21000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। 100 दिन के इस अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों से लाखों लोग जुटेंगे। इस राष्ट्रव्यापी रैली का आयोजन आईएफईवीए (IFEVA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आईसीएटी (ICAT) और एआरएआई (ARAI) जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों का सहयोग भी संस्था को प्राप्त है। ऐसे प्रयास निश्चित रूप से देश के बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने वाले हैं। यदि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय और स्थानीय संस्थाएं भी इस प्रकार के आयोजन कराना प्रारम्भ कर देंगी तो वह दिन दूर नहीं जब देश का कोना-कोना हरा-भरा और प्रदुषण से मुक्त होगा। नई पीढ़ी पर्यावरण को लेकर गंभीर है, आवश्यकता है बच्चों और युवाओं को ऐसे अभियानों में जोड़ा जाए। ग्राम, कस्बों, नगरों और पोश सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक आम और खास जन को ऐसे प्रयास अपने-अपने स्तर पर करने चाहिए। ■

मध्यमवर्गीय परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध का नया कानून

मृत्युंजय दीक्षित
लेखक एवं साहित्यकार

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक नुकसान, युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने तथा नुकसान होने पर आत्महत्या करने व अपराध जगत में जाने से बचाने के लिए "प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल-2025" को संसद के दोनों सदनों से पारित करवा लिया। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद से ही अनेक कंपनियों ने ऑनलाइन मनी गेम ऐप बंद करना प्रारंभ कर दिए।

नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग की सुविधाएं देने वालों पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन या प्रचार करने पर भी दो साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब सरकार का फोकस रियल मनी ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने की रहेगी। विधेयक के अनुसार एक नियामक प्राधिकरण बनाने पर भी काम चल रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की देख-रेख करेगा। कानून का असर उसके बन जाने के पूर्व से ही दिखने लगा क्योंकि इसमें 25 करोड़ से अधिक यूजर्स वाली गेमिंग कंपनी जिसमें विंजी भी शामिल है ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर अपनी सेवाओं को वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही ड्रीम-11, रमी सर्कल जैसी प्रमुख कंपनियों ने भी अपने गेम्स को हटाना प्रारंभ कर दिया है। एमपीएल और जुपी ने भी अपना कारोबार समेट लिया है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग बड़ा कारोबार बन चुका है इसमें लगभग 400 कंपनियों में लगभग दो लाख युवा काम कर रहे थे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एप पर प्रतिबंध लगाकर अपनी आमदनी का भी नुकसान किया है क्योंकि यह कंपनियां जीएसटी में भी 20 हजार करोड़ का योगदान कर रही थीं। सरकार ने अपना मुनाफा

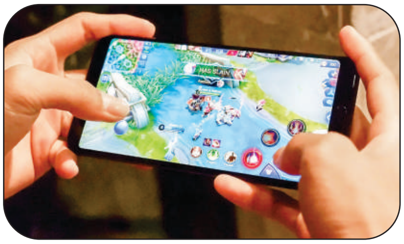

त्यागकर मध्यमवर्गीय परिवार के जो लोग हर वर्ष ऑनलाइन गेमिंग एप्स के चक्कर में पड़कर 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक गंवा देते थे उनका धन बचाने के लिए यह कानून पारित करवाया है। ऑनलाइन गेमिंग से हर साल 45 करोड़ लोगों को नुकसान होता है।

सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है तब भी सरकार ने आम जनता और समाज को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया। सरकार जानती है कि इस खेल में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं जो कोर्ट भी जा सकते हैं तब भी सरकार युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए संकल्पबद्ध व अडिग है। कानून को कोर्ट में चुनौती के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है।

विश्व भर की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की नजर भारत पर है क्योंकि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है। जैसे ही यह कानून पारित होने की खबर सामने आई वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग एप्स की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सदन में बिल पारित होते समय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को विकार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीडी -11 ने इसे गेमिंग विकार घोषित किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इसके कारण लोग मनोवैज्ञानिक विकारों और जुनूनी व हिंसक व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं ऑनलाइन गेमिंग के कारण भारत की परिवार संस्कृति पर भी गहरी चोट पहुंच रही है।

ऑनलाइन गेमिंग एक महत्वपूर्ण विषय है जो डिजिटल दुनिया में व्यापक पैमाने पर उभर रहा है। इसके तीन सेगमेंट हैं जिसमें पहला ई स्पोटर्स है जिसमें टीम बनाकर खेलते हैं, मंथन होता है इसमें हमारे खिलाड़ियों ने पदक भी जीते हैं। इस विधेयक में उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा सेगमेंट ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं जैसे सोलिटेयर, सुडोकू , शतरंज आदि उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा है ऑनलाइन मनी गेम्स जो चिंता का विषय हैं। इसकी एल्गोरिदम अस्पष्ट है, कभी-कभी यह जानना भी मुश्किल होता है कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग एक बड़ी मानवीय त्रासदी बन चुकी है।

विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि-"द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" भारत को गेमिंग नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ई -स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा।" ■

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा - 100 साल की सेवा यात्रा है संघ की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संभाषण में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा, "हमारा स्पष्ट मत है, ये देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, ये देश राजसत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की विधा संभालने वाले नहीं बनाते हैं, ये देश बनता है कोटि-कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों के, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है। व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 100 साल की राष्ट्र की सेवा, एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्ष्यावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, यह जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से, 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। मैं आज यहां लाल किले के प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य, समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा।"

ईमेल का आविष्कारक एक भारतीय किशोर की अनकही कहानी

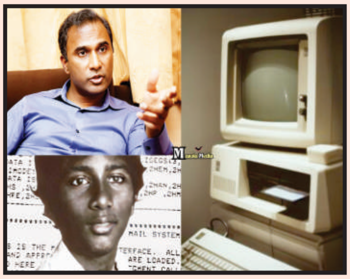

जब भी हम ईमेल खोलते हैं और किसी को संदेश भेजते हैं, शायद ही कभी सोचते हों कि यह अद्भुत सुविधा किसकी देन है। हममें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह किसी अमेरिकी टेक कंपनी या किसी बड़े वैज्ञानिक का योगदान होगा। लेकिन अगर हम कहें कि इस क्रांति की शुरुआत भारत के एक 14 वर्षीय बालक ने की थी, तो क्या आप यक़ीन करेंगे? सच्चाई इससे कहीं अधिक प्रेरणादायक और साथ ही कम जानी-पहचानी है।

साल 1978 में, जब एक सामान्य बच्चा पढ़ाई और खेल में व्यस्त रहता है, तब मात्र 14 साल के भारतीय बालक शिवा अय्यादुरई एक ऐसा कारनामा कर रहे थे, जिसने पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था को नया आयाम दे दिया। उन्होंने दुनिया का पहला पूर्ण ईमेल सिस्टम बनाया। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आज भी इस्तेमाल होने वाली सुविधाएँ- इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, एड्रेस बुक और अटैचमेंट सब शामिल थीं।

सोचिए, एक किशोर जिसने कंप्यूटर और तकनीक की सीमित पहुँच के बावजूद वह बना कर दिखाया, जो आने वाले दशकों तक दुनिया की धड़कन बन गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में बहुत कम लोग उनके नाम से परिचित हैं। इतिहास में उनके योगदान को अक्सर परछाई में रख दिया गया, जबकि अन्य नाम सुर्खियों में छाए रहे।

यह कहानी केवल तकनीक की नहीं है, अपितु भारतीय मेधा, भारतीय संकल्प-शक्ति तथा इस सत्य का द्योतक है कि सृजनात्मक प्रतिभा किसी आयु-सीमा की परिधि में आबद्ध नहीं होती। शिवा अय्यादुरई का कार्य हमें स्मरण कराता है कि भारतभूमि सदा से उन स्वप्नद्रष्टाओं की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने अपने अदम्य परिश्रम और दूरदर्शी दृष्टिकोण से भविष्य की दिशा निर्धारित की।

पर्वत से परोसते सपने

टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करते हुए अचानक एक मोड़ पर नजर ठिठक जाती है-एक खूबसूरत, सादा-सा बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा है- 'कैफे द बुरांश बाइट्स'। बाहरी चमक-दमक से दूर, लेकिन भीतर से भरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मिठास से। यह कैफे सिर्फ भोजन परोसने की जगह नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जो पिथौरागढ़ जिले के कनालीछीना विकासखंड की कुछ महिलाओं ने अपने दम पर लिखी है।

कहानी शुरू होती है मल्लिकार्जुन स्वयं सहायता महिला समूह से। इन महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऋण लिया, और तय कर लिया कि अब वे सिर्फ पहाड़ों की ढलानों पर जीवन नहीं बिताएंगी, बल्कि आत्मनिर्भरता की ऊँचाई भी छूएंगी। उन्होंने अपने अनुभव, मेहनत और पारंपरिक पहाड़ी स्वाद को एक नए रूप में ढालकर शुरू किया-एक आत्मनिर्भर कैफे। कैफे के भीतर कदम रखते ही एक आत्मीय-सी खुशबू आपका स्वागत करती है। गहत की दाल की सोंधी महक, मंडुए की रोटी की गरमाहट, बुरांश के शरबत की ताजगी। हर व्यंजन में एक कहानी है, हर स्वाद में संघर्ष की मिठास। और यही नहीं, इन महिलाओं ने घर में बने शुद्ध शहद, अचार, और मसाले भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराए हैं। जैसे हर चीज में उनकी मेहनत की झलक हो।

उद्घाटन के दिन कैफे में एक खास हलचल थी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जब रिबन काटते हुए कहा-'यह सिर्फ एक कैफे नहीं, एक प्रेरणादायक मॉडल है,' तो आंखों में खुशी के आंसू थे और होंठों पर आत्मगौरव की मुस्कान। ब्रिगेडियर गौतम पठानिया भी जब बोले-'मैं इन महिलाओं को सलाम करता हूँ,' तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा।

यह कहानी सिर्फ पिथौरागढ़ की नहीं है। यह उन हर महिलाओं की कहानी है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित सपने देखती हैं। यह उन पहाड़ियों की कहानी है जो कठिनाइयों से हारती नहीं, बल्कि हर कठिन चढ़ाई को एक नए रास्ते में बदल देती हैं। 'कैफे द बुरांश बाइट्स' एक उदाहरण है कि जब महिलाएं एकजुट होकर किसी दिशा में बढ़ती हैं, तो न केवल अपने जीवन को संवारती हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई दिशा तय करती हैं। यह कैफे सिर्फ भोजन नहीं परोसता, यह सपने परोसता है-पर्वत से, दिल से, हौसलों से। और शायद इसीलिए, अब जब भी पहाड़ों से ठंडी हवा बहती है, तो उसमें बुरांश की खुशबू ही नहीं, इन महिलाओं के जज्बे की भी महक घुली होती है।

व्हाट्सएप से उड़ान

कोरोना काल में जब सड़कों पर सन्नाटा था, बाजारों में ताले थे और छोटे व्यवसायों की सांसें अटकी थीं। इसी कठिन दौर में मथुरा की लवली अग्रवाल ने वो किया, जो बहुतों के लिए सिर्फ कल्पना थी। उन्होंने न केवल अपने डूबते व्यापार को संभाला, बल्कि अपने साथ-साथ सत्तर और महिलाओं की जिंदगी को नई दिशा दे दी। लवली का पारंपरिक कुंदन और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय पहले से ही था, लेकिन महामारी ने ग्राहकों की आवाजाही और बिक्री दोनों पर असर डाला। आमदनी घटने लगी, लेकिन लवली ने हार नहीं मानी। उन्होंने तकनीक को साधन बनाया और अपने व्यवसाय को एक नए रास्ते पर मोड़ा व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल की ओर।उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें अपने पुराने ग्राहकों को जोड़ा। धीरे-धीरे उन्होंने अपने उत्पादों की तस्वीरें डालनी शुरू कीं। फिर जो ग्राहकों को पसंद आया, वह 'ऑर्डर पर तैयार' होने लगा। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइनों को ढाला गया। नतीजा यह हुआ कि उनके गहनों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लवली ने अकेले चलने के बजाय अन्य महिलाओं को भी साथ जोड़ना शुरू किया। शुरुआत में कुछ महिलाएं आईं, फिर संख्या बढ़ती गई और आज यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक फैल चुका है। 70 महिलाएं इस नेटवर्क से जुड़कर घर बैठे ज्वेलरी बना रही हैं। आकर्षक, ट्रेंडिंग और कस्टमर की डिमांड पर आधारित। ये महिलाएं अब प्रति माह 10 से 12 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही हैं, और सबसे अहम बात उन्हें अपने हुनर और मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा है। लवली का यह कदम केवल एक सफल व्यापारिक रणनीति नहीं है, यह 'आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण' का जीता-जागता उदाहरण है। जहां पहले यह काम एक दुकान तक सीमित था, अब वही काम मोबाइल स्क्रीन पर क्लिक भर से नए बाजारों तक पहुंच रहा है। आज लवली न सिर्फ एक सफल महिला उद्यमी हैं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की आशा की किरण बन चुकी हैं। उनकी सफलता इस बात की गवाही देती है कि सच्चा उद्यम वही होता है जो केवल मुनाफा नहीं, मंच और मौका भी देता है।

यह कहानी हमें बताती है कि छोटे-छोटे आइडियाज, जब लगन और दूरदर्शिता से जुड़ते हैं, तो वे क्रांति बन जाते हैं। और जब एक महिला चल पड़ती है, तो उसके साथ सैकड़ों सपने भी उड़ान भरने लगते हैं। लवली अग्रवाल - एक नाम, एक विचार, एक आंदोलन... जो यह कहता है- अगर आप ठान लें, तो व्हाट्सएप से भी दुनिया बदली जा सकती है!

वायु प्रदूषण पर प्रहार: 'पॉल्यूशन कैचर' मॉडल

दशकों से प्रदूषण भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिये गंभीर चुनौती बना हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने-अपने तरीके से इसका हल निकालने की कोशिश में लगे हुये हैं। इसी को देखते हुये बरेली के दसवीं के होनहार छात्र कृष्ण सक्सेना ने कुछ नया करने की ठानी और वायु प्रदूषण पर प्रहार करने के लिये एक स्वदेशी तकनीकी समाधान पेश किया है, जिसका उद्देश्य हवा में मौजूद हानिकारक कणों को हटाकर शुद्ध हवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस परियोजना का नाम रखा है पोल्यूशन कैचर मशीन।

इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे चौराहों या औद्योगिक चिमनियों पर लगाया जा सकता है। मशीन में लगा एक पंखा दूषित हवा को भीतर खींचता है। मशीन के भीतर लगी पेट्रोलियम जैली की परत में हवा के प्रदूषित कण चिपक जाते हैं। दूसरी ओर से शुद्ध हवा बाहर निकलती है। मशीन में एक एअर क्वालिटी इन्डेक्स अर्थात हवा में प्रदूषण मापने का यंत्र लगा हुआ है जिससे प्रदूषण के स्तर का पता चलता है तथा मशीन के साथ जुड़े जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की सहायता से मशीन कहां पर स्थित है इसका भी पता लगाया जाता है। कैमरे की सहायता से जहां पर मशीन लगायी गयी है उसके आस-पास की तस्वीरें केन्द्र तक भेजी जा सकती हैं। जीपीएस और कैमरा आसपास के क्षेत्र में कचरा जलने या प्रदूषण फैलने जैसी गतिविधियों पर सतर्क संदेश भी भेज सकते हैं।

बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) की देखरेख में इस मॉडल का एमबी इंटर कॉलेज बरेली के मैदान में फील्ड-परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के लिये चार-सदस्यीय उच्च स्तरीय परीक्षण समिति बनायी गयी। परीक्षण के दौरान मशीन की कार्यप्रणाली को संतोषजनक पाया गया और ऐक्यूआई में गिरावट को एलसीडी स्क्रीन पर दर्ज किया गया। समिति ने मॉडल को प्राथमिक तौर पर सफल घोषित किया। कृष्ण सक्सेना ने इस मॉडल का पेटेंट फाइल करने के लिए आवेदन भी किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बाहरी वायु प्रदूषण हर वर्ष करीब सत्तर लाख मौतों का कारण बनता है जिसमें स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियाँ प्रमुख हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कृष्ण सक्सेना का स्वदेशी, सस्ता, और पोर्टेबल समाधान सिर्फ तकनीकी नवाचार ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर लाने की जोरदार बानगी है जो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली तकनीक के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बन सकता है।

बिना एसी के घर को ठण्डा करने की स्वदेशी तकनीक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक ऐसी शीट का विकास किया है जो वातानुकूलन या एयरकंडिशनिंग में मदद करेगा। इस पॉलीमर शीट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह इसके ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर धूप को वापस भेज देगी और तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक घट जायेगा, जिससे कमरा या किसी अन्य यंत्र के भीतर गर्मी नहीं लगेगी। खास बात यह है कि इससे खर्चीले एयर कन्डीशन के उपयोग की आवश्यकता नही होगी। इस शीट की कीमत लगभग 50 रूपये प्रति वर्ग फुट है जो महंगे एयर कंडीशिनिंग की लागत के मुकाबले बहुत कम है।

आईआईटी कानपुर के केमिकल इन्जिनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक प्रो. शिवकुमार ने इसका विकास किया है तथा इस शीट की संरचना का पेटेण्ट भी कराया है जिसकी घोषणा अभिव्यक्ति 2025 कार्यक्रम के दौरान आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल ने की। इस दौरान उन्होंने इसे आइसक्रीम बेचने वाली बॉक्स के ऊपर लगाकर दो वेंडर्स को प्रयोग करके दिखाया। जानकारी है कि स्टार्टअप इनक्यूवेशन और इन्नोवेशन सेंटर के साथ मिलकर इसका व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया गया है। बिना बिजली या किसी अन्य उपकरण के यह शीट छत या दीवार पर लगते ही घर का तापमान 10 डिग्री तक घटा देती है। इस प्रकार अगर किसी घर में एयर कंडिशनिंग का

उपयोग किया भी जाता है तो यह तकनीक बिजली का बिल आधा कर देती है। इसका उपयोग करने से विदेशी महंगी तकनीक पर निर्भरता खत्म हो जायेगी। इसके अलावा बारिश, धूल और तेज धूप भी इस तकनीक के आगे बेअसर हैं। इसे लगाने के लिए किसी महंगे फ्रेम की भी जरूरत नहीं, इसे सीधे फिट किया जा सकता है। इसकी सफेद सतह सूरज की किरणों को टकराते ही लौटा देती है, जबकि पॉलीमर कोटिंग बची-खुची गर्मी को अंदर आने से रोक देती है। यह सिर्फ ठंडक देने वाली शीट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का ठोस कदम है जो सस्ती, टिकाऊ और देश में स्वदेशी है।

आपदा में सेवा का संकल्प

विपरीत परिस्थितियों में स्वयंसेवकों की मिसाल

भारत की शक्ति केवल उसकी विशाल जनसंख्या या आर्थिक क्षमता में नहीं, बल्कि सेवा की उस परंपरा में है जिसने हर संकट और चुनौती में समाज को संबल दिया है। विविधताओं से भरे इस देश में जहां समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं से लोगों के जीवन में संकट आ जाता है चाहे भारी बारिश हो, भूस्खलन की समस्या हो या अन्य, इन सभी के बीच तटस्थ होकर समाज को संबल देने के लिए जो पहली पंक्ति में दिखाई देते है वे है स्वयंसेवक जो सेवा परंपरा के वाहक हैं। स्वयंसेवकों ने हर मोर्चे पर समाज के साथ खड़े होकर निःस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। हाल ही में देश के तीन अलग अलग हिस्सों- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं ने यह उदाहरण एक बार फिर सबके सामने रखा।

गुना जिले में राहत और भोजन सेवा : गुना जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। नदी-नाले उफान पर थे और गाँव-शहर दोनों ही क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई। ऐसे समय में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्थानीय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्यों में जुट गए।

तथा दो केंद्रों से 800 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन परोसा गया, साथ ही 300 से अधिक भोजन पैकेट सीधे बस्तियों में पहुंचाए गए। सेवा भारती ने यह भी घोषणा की कि 'अन्नपूर्णा भोजनालय' प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन उपलब्ध कराता रहेगा। संकट की इस घड़ी में स्वयंसेवकों ने यह भरोसा जगाया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा।

प्रयागराज में राहत और मानसिक संबल : प्रयागराज के दक्षिण भाग में बाढ़ का असर गहराई से महसूस किया गया। यहां स्वयंसेवकों ने केवल खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि मानसिक संबल भी बाढ़ पीड़ितों को प्रदान किया। लगभग ढाई सौ से अधिक परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित की गईं। साथ ही स्वयंसेवकों ने भजन और कीर्तन आयोजित कर पीड़ितों में सकारात्मकता का संचार किया। कठिन परिस्थितियों में भी जल और कीचड़ की परवाह किए बिना राहत पहुंचाना स्वयंसेवकों की निष्ठा को दर्शाता है। इस सेवा कार्य में संघ के भाग सह संघचालक माननीय मिल्कियत सिंह बाजवा जी सहित 20 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और निःस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।

बादल फटने और बाढ़ में जीवन रक्षा : 27 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को बुरी तरह झकझोर दिया। दर्जनों लोगों की जान गई और अनेक परिवार बेघर हो गए। ऐसी स्थिति में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बिना समय गँवाए राहत में जुट गए।

धर्मशाला के मनुणी खड्ड क्षेत्र में फंसे लोगों को भोजन और दवाइयां पहुंचाई गईं। मंडी जिले के पंडोह क्षेत्र में पट्टिकरी डैम टूटने के बाद स्वयंसेवकों ने प्रभावित परिवारों तक राशन, कपड़े, दवाइयां और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। थुनाग, करसोग और धर्मपुर जैसे क्षेत्रों में भी तुरंत सेवा कार्य शुरू किए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासनिक मदद से पहले ही स्वयंसेवक वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने न केवल राहत पहुंचाई, बल्कि आशा और भरोसा का भी संचार किया।

प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों में स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक एकजुटता को भी सुदृढ़ बनाती है।

रिश्तों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाता–आपका अपना सूर्या।

सूर्या रोशनी – सिर्फ रोशनी नहीं, भरोसे का नाम है। एक ऐसा भरोसा जो रिश्तों में प्यार की रोशनी भरता है। बात रोज़ की ज़रूरतों की हों या आपकी सुरक्षा की, हमारी कोशिश रही है कि हम – हमेशा आपको कुछ नया दें, और आपके इस भरोसे को और भी मज़बूत बनाएं।

आइए मिलकर इन सुंदर पलों को और भी ज्यादा रोशन करें एवं विकसित भारत की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाएँ।

Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting

I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY

SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya | surya_roshni | surya.roshni | surya-roshni

Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

RNI No. : UPHIN/2023/84344 Postal Reg No. : DL (DS)-61/MP/2023-24-25

सरस्वती शिशु मन्दिर

सी–41, सेक्टर–12, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
दूरभाष: 0120–4545608

ई–मेल: ssm.noida@gmail.com
वैबसाइड: www.ssmnoida.in

विद्यालय की विशेषताएें

* भारतीय संस्कृति पर आधारित व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की शिक्षा।
* नवीन तकनीकी शिक्षा प्रोजैक्टर, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी., कैमरा आदि की सुविधा।
* आर.ओ. का शुद्ध पेय जल, सौर ऊर्जा, विशाल क्रीड़ा स्थल व हरियाली का समुचित प्रबन्ध।
* प्रखर देशभक्ति के संस्कारों से युक्त उत्तम मानवीय व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल।
* सामाजिक चेतना एवं समरसता विकास के लिए विविध क्रियाकलाप।
* विद्यालय को श्रेष्ठतम बनाने की दृष्टि से आपके सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

प्रदीप भारद्वाज	राजीव नाईक	जितेन्द्र गौतम	देवेन्द्र शर्मा
(अध्यक्ष)	(व्यवस्थापक)	(कोषाध्यक्ष)	(प्रधानाचार्य)